बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 131

प्रतिगामी है प्रस्तावित कानून

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करके इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। संबंधित विधेयक को वर्तमान विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है और इसमें कहा गया है कि स्थानीय कंपनियों के रोजगार में प्रबंधन के पदों पर 50 फीसदी और गैर प्रबंधकीय पदों पर 75 फीसदी नियुक्तियां स्थानीय लोगों की होंगी। आश्चर्य नहीं कि इस कानून को लेकर आईटी के केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्रों और फार्मा उद्योग के गढ़ बेंगलूरु में कंपनियों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। ये वे कंपनियां और क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने पहले ही एक वक्तव्य जारी करके अपनी निराशा जाहिर कर दी है और राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की इच्छा व्यक्त की है। स्थानीय रोजगार के कानूनों की प्रक्रिया नई नहीं है। महाराष्ट्र ने 2008 में 80 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देने का कानून बनाया था। आंध्र प्रदेश ने 2019 में 75 फीसदी और हरियाणा ने 2020 में 75 फीसदी स्थानीय रोजगार का कानून बनाया। इन सभी कानूनों को औद्योगिक संगठनों ने अदालत में चुनौती दी। नवंबर 2023 में अदालत ने हरियाणा के कानून को निरस्त किया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसके लिए जो वजह दी वह जानकारी बढ़ाती है।

हरियाणा ने यह कानून बनाया था कि निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये या इससे कम के मासिक वेतन वाले पदों में से 75 फीसदी स्थानीय स्तर पर भरे जाएंगे। उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त करते हुए दो वजह दीं। पहला, खुले बाजार में नियुक्तियां करने का नियोक्ता का अधिकार राज्य सरकार के दायरे से बाहर था। दूसरा, स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार आरक्षित करना अन्य लोगों के विरुद्ध था। न्यायालय ने कहा कि हरियाणा के बाहर के नागरिकों को दूसरे दर्जे का स्थापित करके संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किया गया है। उसने यह भी कहा कि यह आजीविका कमाने के उनके अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है जो सभी नागरिकों को किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की सुविधा देता है और उन्हें पूरे देश में अबाध रूप से कहीं भी आने-जाने की इजाजत देता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का 2019 का कानून असंवैधानिक है लेकिन वह मामले की सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जहां मामले की सुनवाई फरवरी में आरंभ हुई।

संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन के अलावा ऐसी संकीर्णता के पीछे कोई आर्थिक तर्क समझ पाना मुश्किल है। कर्नाटक के विधेयक में 'स्थानीय' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह व्यक्ति राज्य में पैदा हुआ हो, वहां कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो और कन्नड़ भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम हो। इसके अलावा माध्यमिक स्कूली शिक्षा में कन्नड़ भाषा का होना भी जरूरी है। जिन लोगों ने माध्यमिक स्कूल में कन्नड़ भाषा नहीं ली हो उन्हें इस भाषा में कुशल होने की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इससे पहले इस वर्ष के आरंभ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पूछा गया था कि उन्होंने अपने यहां कितने कन्नड़ कर्मचारियों को रोजगार दिया है। रोजगार पर ऐसा चुनौतीपूर्ण ढांचागत प्रतिबंध ऐसे समय में शायद निवेश आकर्षित न कर पाए जब राज्यों के बीच निजी निवेश, खास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर तगड़ी प्रतिस्पर्धा के हालात हैं। प्रतिस्पर्धी बाजारों में संचालित निजी उद्योगों को बेहतरीन प्रतिभाओं को चुनने की आजादी होनी चाहिए। प्रतिभा चयन को ऐसे आधार पर रोकना क्षमता और उत्पादकता पर असर डालेगा। अभी तक देश के राज्यों को देश की सांस्कृतिक विविधता से लाभ मिला है। अब उसे संकीर्ण राजनीतिक लोकलुभावनवाद के लिए सीमित करना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने के समान होगा।

अजय मोहंती



डेटा विश्लेषण और जीएसटी नीति

कर सुधार का सुखद अंत उचित नीतिगत सुधारों पर निर्भर करता है, जिसके लिए शोध संस्था द्वारा गहन अंतर्दृष्टि के लिए जीएसटी डेटा के समृद्ध स्रोत का दोहन करने की जरूरत है। बता रहे हैं वी एस कृष्णन

कहा जाता है कि डेटा ही नया तेल है। यह भी कहा जा सकता है कि डेटा वह अमृत है जिसे नीति निर्माताओं को पीने और पचाने के बाद अच्छी नीति का निर्माण करना चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम के हालिया अध्ययन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर इस दावे की सच्चाई सामने ला दी है।

एक निष्कर्ष यह है कि जीएसटी का राजस्व संबंधी प्रदर्शन बढ़ाचढ़ा हुआ है क्योंकि विशुद्ध राजस्व के बजाय सकल राजस्व पर विचार किया गया। ऐसा इसलिए कि एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी रीफंड का बड़ा हिस्सा निर्यातकों को रीफंड किया जाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसटी के 0.7 से 0.8 फीसदी के बराबर होता है। ऐसे में 2023-24 में जीएसटी-जीडीपी अनुपात जीएसटी के पहले के 6.1 फीसदी के स्तर तक पहुंच गया। अगर इस बारे में पहले जानकारी होती तो शायद जीएसटी दरों में कमी करने के लिए 2017-18 और 2018-19 में जो प्रयास किए गए वे और अधिक कठोर होते और चुनिंदा वस्तुओं में इजाफा करके दरों में कटौती को संतुलित कर दिया जाता ताकि राजस्व निरपेक्षता बरकरार रहे।

अध्ययन के नतीजों से एक अहम तथ्य सामने आया: हमने जीएसटी डेटा के अहम स्रोत का पूरा उपयोग नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि इसे हमारे विश्वविद्यालयों के तमाम निजी शोध संस्थानों तथा सार्वजनिक फाइनैंस समूहों के लिए खोल दिया जाए। इसमें नीति निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण शोध के क्षेत्र कौन से हैं? पहला, अंतर्राज्यीय व्यापार का क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। जब जीएसटी के क्रियान्वयन पर बहस हो रही थी, तब यह दावा किया गया था कि प्रवेश शुल्क और चुंगी यानी तथाकथित 'सीमा कर' को समाप्त करने से अंतर्राज्यीय व्यापार बढ़ेगा। द इकनॉमिस्ट ने अपनी हालिया विशेष रिपोर्ट में कहा कि जीडीपी के हिस्से के रूप में अंतर्राज्यीय व्यापार 2017 से 2021 के बीच 23 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो गया। हमें आईजीएसटी डेटा तथा अन्य डेटा का इस्तेमाल करके इस दावे की गहराई से पड़ताल करनी होगी। यह जानना जरूरी है कि क्या जीएसटी के बाद भारतीय बाजार का विस्तार हुआ है और किन राज्यों को लाभ हुआ है।

एक अन्य अहम क्षेत्र है छोटे कारोबारों और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की कुल प्रक्रिया पर जीएसटी का प्रभाव। छोटे कारोबारों की श्रेणी में एकरूपता नहीं है। जीएसटी सुधारों के जरिये उन सभी छोटी सेवा कंपनियों की तकदीर सुधरनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें पूंजीगत वस्तुओं पर चुकता किए गए कर पर क्रेडिट का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए था। नीतिनिर्माताओं को जहां इस विश्लेषण की प्रतीक्षा है वहीं सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करेंगे?

पहली बात, दरों को युक्तिसंगत बनानेकी जरूरत है ताकि जीएसटी प्राप्ति में और सुधार हो। जीएसटी अध्ययन सुझाता है कि 'खराब और नुकसानदेह वस्तुओं' को जीएसटी दर ढांचे में शामिल करने के बाद भी उपकर जारी रखा जाए। सरकार ने एक मंत्री समूह समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता अब बिहार के वित्त मंत्री कर रहे हैं। समिति के सामने एक कठिन काम है। उसे राजस्व निरपेक्षता बरकरार रखने और मुद्रास्फीति के दबाव से बढ़ने के दौरे दायित्व को निभाना है। समिति के लिए कुछ ठोस विचार इस प्रकार हैं:

पहला, मानक जीएसटी दर को 18 फीसदी से कम करके 16 फीसदी करना चाहिए। यह एक अहम संकेत होगा कि सरकार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की लागत को कम करना चाहती है। यह जानना जरूरी है कि मानक दर को कम करने के लिए दोनों सिरों पर उत्पादों पर दर बढ़ानी होगी। जीएसटी राजस्व में नुकसानदेह वस्तुओं पर लगने वाले कर की हिस्सेदारी 16 फीसदी है जिसे 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया जाना चाहिए। 12 फीसदी की दर को 16 फीसदी की दर में मिला दिया जाना चाहिए। कपड़ा और औषधि क्षेत्र को इसका अपवाद माना जा सकता है। औषधि क्षेत्र के मामले में दरों को 12 फीसदी से कम करके आठ फीसदी किया जा सकता है और कपड़ा क्षेत्र में दरों को 5 से 12 फीसदी के बीच की दर के बजाय आठ फीसदी की एक दर लागू की जा सकती है। स्वर्ण और आभूषणों पर तीन फीसदी की दर को बढ़ाकर 6 फीसदी किया जा सकता है ताकि मानक दर कम करने से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

सभी रियायतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा और इन वस्तुओं को 8 फीसदी की दर वाले दायरे में रखना होगा। केवल उन्हीं वस्तुओं को रियायत मिलनी चाहिए जिन्हें जीएसटी के पहले के दौर में मूल्यवर्धित कर से रियायत मिलती थी।

आखिर में जीएसटी के तहत हर प्रकार की रियायत कम करने की आवश्यकता है। यह समझने की जरूरत है कि रियायतें अंततः नुकसानदेह साबित होती हैं क्योंकि वे कारोबारों को इनपुट कर क्रेडिट से वंचित करती हैं। एक अन्य लाभ यह होगा कि कर चोरी में कमी आएगी, क्योंकि अक्सर छूट प्राप्त इकाइयों के नाम पर अक्सर फर्जी चालान जारी किए जाते हैं। ऐसे में 8 फीसदी, 16 फीसदी और 40 फीसदी के स्लैब के साथ तीन स्तरीय जीएसटी ढांचा तथा सीमित रियायतें जीएसटी राजस्व बढ़ाएंगी और मानक दर में कमी के साथ विनिर्माण को गति देंगी। दरों को तार्किक बनाने की इस कवायद को आपूर्ति पक्ष पर पुनर्गठित टैरिफ नीति द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता होगी। जैसा कि प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने कहा है, यह जरूरी है कि सीमा शुल्क की दर को वर्तमान 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत या उससे कम किया जाना चाहिए। इसके तहत हम तीन स्तरीय संरचना बना सकते हैं जिसमें कच्चे माल पर सबसे कम दर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर थोड़ी अधिक दर तथा तैयार माल पर सबसे अधिक दर होगी। इससे इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे में सुधार होगा और अहम कच्चा माल तथा घटक हमारे विनिर्माण उद्योग को मिल सकेंगे। इन बदलावों को आगामी बजट में भी अंजाम दिया जा सकता है। जीएसटी कर सुधारों को अगर इस ढंग से अंजाम दिया गया तो ये कर-जीडीपी अनुपात को मौजूदा 18 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक पहुंचा सकते हैं। बेहतर कर-जीडीपी अनुपात सरकार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय बढ़ाने में मदद करेगा, मसलन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में।

कुल मिलाकर अगर समुचित नीतिगत सुधार किए जाएं तो जीएसटी का सुखद समापन हो सकता है। इससे विनिर्माण के क्षेत्र में भी एक तरह का पुनर्जागरण आएगा। खासतौर पर श्रम गहन विनिर्माण में क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कपड़ा, जूते-चप्पल, हल्की इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिलता है। इससे इन क्षेत्रों के लिए भी मारुति जैसा अवसर बना सकता है। केवल तभी हम जनांकिकीय लाभ मिल सकेगा। हमारे नीति निर्माताओं का देश के युवाओं के प्रति यह दायित्व है।

(लेखक सीबीआईसी के सदस्य रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

जलवायु परिवर्तन: जीवन और मौत का सवाल?

हम यह जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर मौसम पर भी पड़ता है जिससे लोगों की जिंदगी और आजीविका के साधन दोनों ही प्रभावित होते हैं। लेकिन हम इस बात पर पर्याप्त चर्चा नहीं करते हैं कि मौसम के ये चरम स्तर लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। इस निराशाजनक दौर में जब तापमान सहन की क्षमता से ऊपर चला गया, तब हमें पता चला कि गर्मी भी जानलेवा हो सकती है। हमें यह भी मालूम हुआ कि न्यूनतम तापमान में वृद्धि यानी रात की गर्मी भी मौत का कारण बन सकती है। यह निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है कि हम बदलते जलवायु संकट और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बीच की कड़ियों को जोड़कर देखें।

इस साल दुनिया भर में झुलसाने वाली गर्मी पड़ी और इस भीषण गर्मी के कारण लोगों की जान भी गई। दिल्ली में जून महीने के आखिर तक यह अनुमान था कि अधिक गर्मी से करीब 270 लोगों की मौत हो गई। लेकिन मैं इस संख्या को सावधानी से देखती हूं। दरअसल हमें यह मालूम नहीं कि कितने लोगों की मौत सिर्फ गर्मी की वजह से हुई क्योंकि जिन लोगों को हृदय या गुर्दे की बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी मुश्किलें गर्मी के कारण और बढ़ जाती है। संभव है कि इस गर्मी के मौसम में कई लोग केवल भीषण गर्मी का शिकार हो गए हों, लेकिन डॉक्टरों ने इसके लिए पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को ही इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

हम जानते हैं कि गर्मी के कारण वैसे लोग अधिक जोखिम की स्थिति का सामना करते हैं जिनकी काम की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं जिसके कारण उन्हें धूप में रहना पड़ता है जैसे कि निर्माण कार्य से जुड़े कामगार या फिर किसान। इसके अलावा गरीब तबके के लोगों को भी इसी तरह के जोखिम से जूझना पड़ता है क्योंकि उनके पास बिजली की सुविधा नहीं होती है और वे खुद को ठंडा रखने के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी मौत की वजहों में गर्मी नहीं गिनी जाती है और यह मान लिया जाता है कि वे गरीब या बूढ़े हैं और उनकी मौत किसी 'अज्ञात कारणों' की वजह से हुई है। इसके अलावा भीषण गर्मी का शिकार होने जैसी स्थिति को कोई अधिसूचित बीमारी में नहीं गिना जाता है जिसका अर्थ यह भी है कि आगे किसी भी कार्रवाई के लिए गर्मी से जुड़ी परेशानी की बात दर्ज किए जाने या इससे जुड़ी सूचना मुहैया करने की जरूरत नहीं पड़ती है।

इसलिए हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हाल की भयानक गर्मी के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ने वाले बोझ और इसके कारण हुई मौतों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है।

हालांकि शोध अब भयानक गर्मी के विभिन्न आयामों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, यह समझा जा रहा है कि रात के वक्त गर्मी बढ़ने से अधिक तादाद में मौत होती है। एक ब्रितानी मेडिकल जर्नल, 'दि लैंसेट' के 2022 के एक शोध पत्र में यह पाया गया कि ठंडी रातों वाले तापमान की तुलना में गर्म रात वाले दिनों में मृत्यु का जोखिम 50 फीसदी से अधिक हो सकता है। इस शोध पत्र के लेखकों का कहना है कि गर्मी के कारण लोगों की नींद भी प्रभावित होती है और इसके चलते शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य से जुड़े तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है।

दूसरा, हम यह जानते हैं कि वाष्पीकरण हमारे शरीर को ठंडा करने का एक तरीका है लेकिन यह तब प्रभावी नहीं होता है जब आर्द्रता 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है और इसे वेट बल्ब घटना कहते हैं। इसलिए न केवल तापमान बल्कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी की स्थिति को समझने की सख्त जरूरत है।

चिंता की बात यह है कि हम इन सभी तीन जानलेवा कारकों में बढ़ोतरी का रुझान देख रहे हैं खासतौर पर शहरी केंद्रों में। यहां तापमान मानवीय सहनशीलता के स्तर से ऊपर बढ़ रहा है और इसके साथ ही आर्द्रता और रात के वक्त गर्मी भी बढ़ रही है। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट में मेरे एक सहयोगी की एक ताजा रिपोर्ट में भारत के प्रमुख शहरों में गर्मी के रुझान पर नजर रखी गई और यह पाया गया कि देश के औसत तापमान के विपरीत शहरों की वायु के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अधिक आर्द्रता वाली गर्मी देखी जा रही है और पिछले से पिछले दशक 2001-10 की तुलना में 2014-23 के दशक के मुकाबले 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है। केवल बेंगलूरु में गर्मी के आर्द्रता के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई और इस पर और जांच की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में यह पाया गया कि सभी जलवायु क्षेत्रों के शहरों में रात में ठंड नहीं होती है। इसमें यह बताया गया कि 2001-10 के दशक में गर्मी के मौसम में रात का तापमान दिन के शीर्ष स्तर के तापमान से 6.2 डिग्री सेल्सियस -13.2 डिग्री सेल्सियस (विभिन्न शहरों में) तक कम हो गया।



जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

लेकिन पिछली 10 गर्मियों के सीजन में, दिन और रात के तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के बीच का यह अंतर कम हो रहा है। हैदराबाद में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, दिल्ली में 9 प्रतिशत और बेंगलूरु में यह 15 प्रतिशत तक है। कोलकाता में पहले से ही दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम था और अब उच्च आर्द्रता स्तर के कारण इसकी स्थिति और भी खराब हो गई है।

हम जानते हैं कि यह सब हमारी दुनिया के दौरे झटके का हिस्सा है। एक तरफ, ग्रह गर्म हो रहा है और इस साल ने पिछले सभी उच्च तापमान के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे भी खराब बात यह है कि अनियमित बारिश, भीषण गर्मी और हवा के रुख में बदलाव से मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। इससे गर्मी और अधिक तनावपूर्ण और घातक हो जाती है। दूसरी ओर, हमारे शहरों में स्थानीय स्तर पर औसत तापमान में नाटकीय बदलाव देखने को मिल रहा है हरियाली वाली जगहों का स्थान कंक्रीट निर्माण के लेने से गर्मी का प्रभाव और बढ़ जाता है। साथ ही यातायात और शीतलन के लिए ऊर्जा के उपयोग से हवा में गर्मी और बढ़ जाती है।

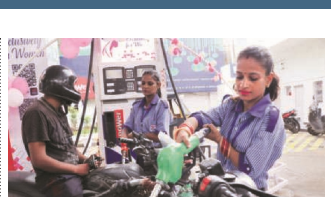
इस दौर ने हमें गर्मी से जुड़े दबाव-तनाव के बारे में नए सबक सिखाए हैं। तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन में मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ ही हमें ऐसी कई बातों से हैरान करने की क्षमता है। अब भी इस विज्ञान को समझना बाकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य पर ज्यादा पड़ेगा। यही कारण है कि ग्रह की जैसी स्थिति होगी उसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि जलवायु परिवर्तन अस्तित्व से जुड़ा संकट क्यों है और यह वास्तव में जीवन और मौत के सवाल से भी जुड़ा है।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

आपका पक्ष

पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में लाए सरकार

जीएसटी लगने के सात वर्ष बाद भी 'एक देश एक कर' का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। आज भी डीजल -पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और कच्चे तेल के साथ ही शराब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। कर और शुल्क के हिसाब से देखा जाए तो केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क ले रही है। राज्य सरकारें भी पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाती हैं। वर्तमान कर व्यवस्था के तहत उत्पादन के प्रत्येक चरण पर केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों के कारण देश में डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना कई तरह से लाभप्रद है। जैसे देश भर में इनकी मानक दरें तय होने से कीमतों में एकरूपता



पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर देश भर में इनकी मानक दरें तय होने से कीमतों में एकरूपता आएगी

आएगी। फिलहाल विभिन्न राज्यों में इनकी कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक का अंतर देखने को मिलता है। इस व्यवस्था से कीमतों में भी कमी की संभावना रहेगी जिसका सकारात्मक असर परिवहन और माल भाड़े की दरों पर पड़ेगा। ऊंचा मालभाड़ा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण होता है। अतः केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाकर एक देश एक कर की व्यवस्था को पूर्णता देनी चाहिए। वैसे इसके लिए राज्यों के साथ सहमति बनाना मुश्किल काम है क्योंकि यह सभी राज्यों के राजस्व का मुख्य स्रोत है। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लगाने के बाद मिलने वाले राजस्व का राज्यों में न्याय संगत वितरण कर इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

विमलेश पगारिया, इंदौर

सेब बागवानों को न हो परेशानी

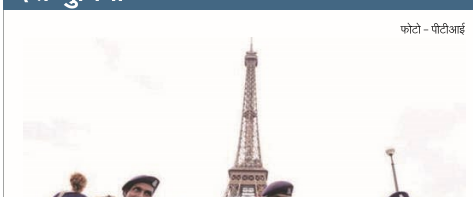
हिमाचल प्रदेश का सेब सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर प्रदेश में सेब की पैदावार बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाएं और सेब बागवानों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो इसका प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। यह बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार का भी अच्छा साधन बन सकता है। सेब का सीजन शुरू हो चुका है। सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की ताकत बढ़ाता है। इस साल सेब की पैदावार अच्छी हुई है। सरकार हर साल किसानों से सेब लेकर इसे दूसरे राज्यों में भेजने के लिए इंतजाम करती आ रही है, लेकिन इस वर्ष प्रदेश में बहुत बारिश होने के कारण बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में किसानों को सेब को दूसरे स्थानों तक भेजने में मुश्किल हो रही है। सरकार को इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, ताकि सेब समय पर बिकने के लिए प्रदेश से बाहर भेजा जा सके। अगर हिमाचल का सेब समय पर प्रदेश और देश की मंडियों में पहुंचेगा तो यह किसानों और सरकार दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रदेश सरकार को केंद्र के साथ मिलकर राज्य के सेब को दूसरे देशों में भेजने के लिए कदम उठाने चाहिए। निर्यात की राह और आसान बनानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई



पेरिस के एफिल टावर के पास बुधवार को सीआरपीएफ के विशेष रूप से प्रशिक्षित श्वान पांच वर्षीय 'वास्ट' और तीन वर्षीय 'डेन्वी'। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और विशेष कमांडो बल के विशेष रूप से प्रशिक्षित 10 श्वानों का दस्ता पेरिस ओलिंपिक के विभिन्न आयोजन स्थलों पर आतंकवाद विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों विरोधी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए फ्रांस में है।

स्थानीय को आरक्षण

कर्नाटक में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की कवायद पर जहां खुशी का इजहार किया जा रहा है, वहीं इसके विरोधी भी कम नहीं हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो एक्स पर आधिकारिक रूप से एक संदेश भी पोस्ट कर दिया था। संदेश बहुत स्पष्ट था कि कर्नाटक में सी और डी ग्रेड की तमाम निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट हटा ली। अब कर्नाटक सरकार की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ है, उसके अनुसार, राज्य में निजी कंपनियों की नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण गैर-प्रबंधन भूमिकाओं के लिए 70 प्रतिशत और प्रबंधन स्तर के पदों के लिए 50 प्रतिशत है। दरअसल, कर्नाटक तेजी से उभरता हुआ राज्य है और बड़ी संख्या में यहां आईटी कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। जब इन तमाम कंपनियों में आरक्षण लागू हो जाएगा, तब जाहिर है, कर्नाटक के बाहर से आए लोगों के लिए वहां रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

कर्नाटक का यह फैसला स्थानीय रूप से भले ही वहां की राजनीति को पसंद आए, पर यदि अपेक्षाकृत रूप से विकसित हर राज्य ऐसे ही आरक्षण का सहारा लेने लगे, तो उन राज्यों का क्या होगा, जो पिछड़े हुए हैं और जहां जरूरत के हिसाब से बहुत कम रोजगार उपलब्ध है? मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि 'हमारी सरकार की आकांक्षा है कि कन्नड़ भूमि में किसी भी कन्नड़ को नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। हमारी सरकार कन्नड़ समर्थक है।' वास्तव में कर्नाटक राज्य अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कानून बनाने जा रहा है और इस विधेयक की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए।

कर्नाटक में जब तमाम निजी कंपनियों में यह आरक्षण लागू हो जाएगा, तो जाहिर है, राज्य के बाहर से आए लोगों के लिए वहां रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए अगर यह आदर्श विधेयक है, तो क्यों न हरेक राज्य इस लागू करें? हालांकि, इसमें उन राज्यों को बहुत नुकसान होगा, जहां निजी नौकरियां कम हैं। सरकारी स्तर पर तो समय-समय पर कुछ राज्य स्थानीय लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के सहारे स्थानीय लोगों को खुश करने की यह कोशिश काबिल-ए-गौर है। विरोध के बावजूद, लगभग तय है कि यह रोजगार संबंधी विधेयक गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा।

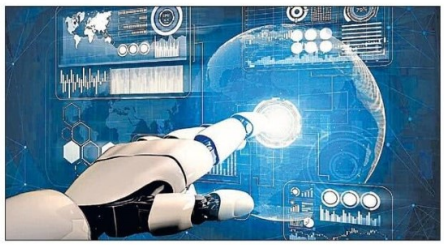
दरअसल, यह मामला केवल स्थानीय राजनीति से नहीं, बल्कि भाषा की राजनीति से भी जुड़ा है। कर्नाटक सरकार यह कोशिश कर रही है कि राज्य में नौकरी के लिए कन्नड़ ज्ञान को अनिवार्य बना दिया जाए। वैसे, राज्य के ही कई उद्यमियों ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है और आशंका जताई जा रही है कि इससे तकनीकी उद्योग को नुकसान हो सकता है। इस फैसले को फासीवादी और असांविधानिक भी कहा जा रहा है। एक आशंका यह भी है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी सरकारी अधिकारियों का दखल बढ़ जाएगा। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वैसे, सरकार रोजगार के अभाव में ही यह कदम उठा रही है। दरअसल, आज न सिर्फ कर्नाटक, बल्कि देश के तमाम राज्यों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की जरूरत है और यह प्रस्तावित विधेयक इसी ओर इशारा कर रहा है।

तकनीकी आजादी की ओर बढ़े भारत



भाविश अग्रवाल | सीईओ, ओला कैब्स

विकास और प्रतिस्पर्द्धा में आगे रहने के लिए हमें एआई और नई ऊर्जा जैसी तकनीक को प्राथमिकता देनी होगी। यही रास्ता है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे।



पिछले दस साल में भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी होकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। हमारा लक्ष्य है, 2047 तक भारत विकसित देश बने। अगर हम अपनी आर्थिक विकास दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर लें, तो भारत 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया भर में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, खासकर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और नई ऊर्जा के क्षेत्र में। हमारे समकक्ष देश, जैसे चीन, नई तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं, पारंपरिक उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं और नए क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत के विकास और प्रतिस्पर्द्धा में आगे रहने के लिए हमें एआई और नई ऊर्जा जैसी तकनीक को प्राथमिकता देनी होगी। इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। ध्यान रहे, साल 1947 में हमने अपनी राजनीतिक आजादी पाई थी और साल 2047 में हमें अपनी तकनीकी आजादी हासिल करनी है। हमें तकनीकी उन्नति के लिए अपनी खुद की रणनीति बनानी होगी। अपने देश में तकनीक का यह उपयोग सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी होना चाहिए।

भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है, लेकिन कंप्यूटिंग में हमारी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। आईटी सेवाओं में हमारी बड़ी सफलता के बावजूद 30 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भारत का हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत है। यहां निवेश की बड़ी जरूरत है। भारत अभी भी अनेकों ताकतों से लैस है। विश्व के सबसे बड़े डेवलपर समुदाय में से एक भारत में है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सिलिकॉन डिजाइनर, विशाल मात्रा में उत्पन्न डाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा आईटी उद्योग हमें एआई में अगणी बनाने की स्थिति में लाते हैं। हम एआई महाशक्ति में बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही, जैसे चीन ने वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत को डाटा, कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम में विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए।

भारत दुनिया का 20 प्रतिशत डाटा बनाता है, लेकिन हमारा 80 प्रतिशत डाटा विदेश में स्टोर किया जाता है, एआई में प्रोसेस किया जाता है और फिर डॉलर में भुगतान करके वापस आयात किया जाता है। यह डाटा कॉलोनाइजेशन इंस्टइंडिया कंपनी के तौर-तरीकों की याद दिलाता है, जहां भारत के कच्चे माल का दोहन करके, उन्हें प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में महंगे दामों पर भारतीयों को बेचा जाता था। आज, हमारे डिजिटल कच्चे माल, यानी डाटा का इसी तरह से लाभ उठाया जा रहा है। हमें अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके गोपनीयता-संरक्षित डाटासेट बनाना चाहिए। हम अपनी डीपीआई की सफलता (जैसे, यूआईडीएआई, यूपीआई, ओएनडीसी) पर आधारित होकर एक नई, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, जो भारत के सिद्धांतों पर आधारित हो।

बेशक, साल 2030 तक 50 गीगावाट डाटा सेंटर की क्षमता पाने के लिए 200 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यह हासिल करने योग्य लक्ष्य है। भारत सिलिकॉन डिवलपमेंट और डिजाइन टैलेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर भी, हमारे पास भारत में डिजाइन किए गए चिप्स की कमी है। हमें इंडस्ट्री लीडिंग चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स और रिसर्च-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि रोजगार बढ़े, भारत में काम करने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं और बेहतरीन वैज्ञानिकों को आकर्षित किया जा सके।

पर्याप्त रोजगार वाले विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा आपूर्ति शृंखला और तकनीक का भी विकास होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है। भारत को इस बदलाव में सबसे आगे रहना चाहिए। नई ऊर्जा का पूरा इकोसिस्टम तीन स्तंभों पर टिका है : रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहन। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब अक्षय ऊर्जा में भारत की ताकत बढ़नी चाहिए। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 में 72 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 175 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। सोलर एनर्जी क्षमता 3.8 गीगावाट से बढ़कर 88 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। वैसे, हम इस मोर्चे पर पीछे हैं। हमें 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

अक्षय ऊर्जा को प्रभावी बनाने के लिए हमें इसे मजबूत बैटरी स्टोरेज से जोड़ना होगा। अभी हमारी बैटरी स्टोरेज क्षमता सिर्फ दो गीगावाट है, जबकि चीन की 1,700 गीगावाट है। अपने अक्षय ऊर्जा ग्रिड को पावरदेने और 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को पाने के लिए 1,000 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, तो भारत में अभी प्रति 1,000 लोगों पर 200 से भी कम इलेक्ट्रिक वाहन हैं। चीन के तीन करोड़ की तुलना में भारत में हर साल सिर्फ बीस लाख ईवी बेचे जाते हैं। भारत को साल 2030 तक पांच करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह बदलाव पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, परिवहन लागत को कम करेगा।

वर्तमान में, सौर ऊर्जा उत्पादन, लिथियम सेल उत्पादन और ईवी उत्पादन जैसे न्यू एनर्जी इकोसिस्टम का 90 प्रतिशत हिस्सा चीन में है। अपनी खुद की तकनीक और आपूर्ति शृंखला बनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक ऊर्जा-कुशल बना सकते हैं और देश में लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं।

भविष्य की तकनीकों में महारत हासिल करना ही भारत के लिए स्लोबल लीडरशिप का रास्ता है। हमें पीछे नहीं रहना है, बल्कि समकक्षों को पीछे छोड़कर एआई और नई ऊर्जा के क्षेत्र में लीडर बनना है। यह भारत को दुनिया में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलने का मौका है। सबसे बड़ी बात कि इससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें समाज के सभी तबकों के एकजुट प्रयास की जरूरत है। जिस तरह हर भारतीय ने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब हमारे तकनीकी भविष्य के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका है। यह सामूहिक कदम उठाने और बड़े सपने देखने का समय है। हमें तत्काल काम शुरू करना होगा, ताकि हम उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बाबा साहेब को भूलकर फर्जी बाबाओं के चक्कर में समाज



श्योराज सिंह 'बेचैन' | प्रोफेसर, दिल्ली विवि

उत्तर प्रदेश के हाथरस में अंबेडकरवादी, लोहियावादी, दलित-पिछड़ा वर्ग राजनीति, दलित साहित्य और अन्य पिछड़ा व बहुजन साहित्य की नाकामी का बहुत बड़ा प्रमाण उपस्थित हुआ, जिस पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस सामदी को भूलना मुश्किल है। सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि 'बाबा' के तथाकथित सत्संग में आखिर 121 मौतें कैसे हो गईं?

सबसे त्रासद यह कि अधिसंख्य मौतें दलित व अतिपिछड़े समाज की महिलाओं और नाबालिग बच्चों की हुई हैं। ज्यादातर मृतक महिलाएं ऐसे परिवारों से तात्कालिक रखती थीं, जिनमें बाबा साहेब आंबेडकर की शिक्षाओं की चर्चा होती है। गौर करने की बात है कि साल 1990 के बाद से ही बहुतों के घरों में बाबा साहेब की तस्वीरों के बरक्स नाना प्रकार के कथित बाबाओं की तस्वीरें प्रवेश पाने लगी हैं। आज जगह-जगह बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं, परइनका कोई प्रभाव वंचित जातियों में दिखाई नहीं देता है। पढ़े-लिखे अफसर और अनेक दलित नेता या तो राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं या फिर कथित बाबाओं के लिए चंदा जुटाते दिखते हैं। अफसोस, बड़ी संख्या में ऐसे वंचित लोग हैं, जो बाबा साहेब को न तो कितावें पढ़ते हैं और न ही उनकी शिक्षा को याद करते हैं।

आज फर्जी बाबाओं के चक्कर लगाने वालों में दलितों और महिलाओं की बड़ी संख्या है। मगर इनकी स्थिति में यही लोग ज्यादा नुकसान में रहते हैं।

वरिष्ठ नेता कांशीराम ने एक समय दावा किया था कि हमने बसपा के *बहुजन संगठक* पत्र और बहुजन प्रचार के जरिये बाबा साहेब के विचारों को उत्तर प्रदेश के घर-घर में पहुंचाया है, जबकि वह प्राथमिक शिक्षा भी ग्रामीण दलित महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाए थे। ध्यान देने की बात है, सन् 1956 में बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, तब महाराष्ट्र की अल्पशिक्षित व अशिक्षित महिलाओं ने अपने-अपने घर से आंडबरी बाबाओं की तस्वीरें और मूर्तियां निकाल बाहर फेंक दी थीं और आंबेडकरी विचार-प्रचार के लिए समर्पित संस्थाओं, व्यक्तियों, मलाईचाट अफसरों और नेताओं को आत्म-विश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया था।

हाथरस हादसे के हवाले से अगर सोचें, तो प्रभावहीनता, नाकामियां कहां हैं? जिम्मेदार कौन हैं? दलित साहित्य चेतना और दलित राजनीति ने तथाकथित बाबाओं के आंडबरों से दलित समाज को दूर तो किया है, पर वह खालीपन न तो शिक्षा से भरा गया, न रचनात्मक सांस्कृतिक क्रियाकलाप उन तक पहुंच पाए। ज्ञान की सत्ता और विचारों की प्रगति के बारे में सोचा भी नहीं जाता है। ऐसे में, दलितों और महिलाओं की स्थिति सबसे खराब हो जाती है।

आज फर्जी बाबाओं के चक्कर लगाने वालों में दलितों और महिलाओं की बड़ी संख्या है। भगदड़ की स्थिति में यही लोग ज्यादा मारे जाते हैं। अंधविश्वास के चंगुल में आकर जो लोग मारे गए हैं, उनकी पृष्ठभूमि पर जरूर गौर करना चाहिए। ढोंगी बाबाओं के पास जाने वाले लोग अपनी तर्क-बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते? अंधविश्वासों के सहारे तरक्की की सीढ़ियां क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराष्ट्र में एक समय हजारों महिलाएं ढोंगी बाबाओं के आधामंडल को झटक बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर बढ़ीं और उन्होंने अपने परिवारों को भी सुधारा। उन पर *हमने भी इतिहास रचा है* (आम्ही इतिहास गढ़वला) शीर्षक से मीनाक्षी मून और उर्मिला पवार के संपादन में एक खास पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो आज भी महिला जागृति का बहुमूल्य दस्तावेज है।

उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में राजनीति ने दलितों और महिलाओं को बहुत ऊंचे सपने दिखाए हैं और खासकर दलित स्त्री-समाज को साहित्य, संगीत, कला विहीन रखकर उनके बौद्धिक विमर्श को रसातल में पहुंचा दिया है। संत कबीर, रैदास से लेकर आज तक अनेक शीर्ष दलित लेखक, संत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, पर तब भी यहां किसी ढोंगी बाबा को लोग ईश्वर मानने लगते हैं। आंबेडकरवादी दलित लेखकों को लगता था कि उनकी कविताओं, कहानियों, लेखों ने असर डाला है, नेताओं को लगता था कि उनके भाषणों से चेतना जागृत हुई है, पर हाथरस हादसे के बाद सबको सोचने पर मजबूर होना चाहिए। बाबा साहेब का एक नारा था, 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो', इसे लोगों के बीच फिर बार-बार दोहराने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अच्छे-बुरे में बांटना

लोग हमेशा यह मानते हैं कि वे अच्छे हैं और कोई दूसरा बुरा है। यही एकमात्र तरीका है, जिससे वे संसार में अपना अभियान जारी रख सकते हैं।... लेकिन कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सीमा के किस तरफ हैं? भारत अच्छा है या पाकिस्तान? आप सीमा के इस तरफ हैं, तो जाहिर है कि भारतीय अच्छे हैं; पाकिस्तानी बुरे हैं। अगर आप सीमा के उस पार होते, तो आप दूसरे पक्ष के लिए बहस करते। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं। उसी के अनुसार आप 'अच्छे' और 'बुरे' होते हैं। आप उसके परे नहीं सोच सकते।

आपकी सोच स्वयं आपकी पहचान तक सीमित है। चूंकि आपकी पहचान हमेशा सीमित होती है, इसलिए सोच भी सीमित है। फिर इन सीमाओं के साथ आप यह निर्णय लेने की मुखर्ता में क्यों पड़ते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? जैसे ही आप किसी चीज को अच्छे या बुरे के रूप में पहचानते हैं, आप दुनिया को विभाजित करते हैं।

अब जब कोई आकर मुझसे कहता है कि वह अध्यात्म-मार्ग पर चलना चाहता है, तो मैं उससे यही कहता हूं, 'ठीक है, एक हफ्ता यहां ठहरो। हम देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।' एक ने कहा, 'शनिवार को मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन है; मुझे जाना होगा। मैं सिर्फ तीन दिन ही यहां रह सकता हूं।' मैं उससे पूछता हूं, 'अच्छी बात है, लेकिन इस मार्ग पर आप कितनी दूर जाना चाहेंगे?' वह कहता है, 'पूरा मार्ग तय करूंगा।' फिर मैं कहता हूं, 'मात्र तीन दिनों में पूरा मार्ग? कोई बात नहीं, जब तक आप यहां हैं, हम चीजों को कीजिए, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है।' तब वह कहता है, 'नहीं, यह मुझे पसंद नहीं है।' फिर मैं उससे कहता हूं, 'ठीक है, जो चीजें पसंद हैं, उनकी एक सूची बनाकर मुझे दीजिए। हम केवल वही करेंगे।' वह व्यक्ति वहां बैठकर कुछ देर गंभीरतापूर्वक सोचता है और आधा दर्जन चीजें लिखता है। तब मैं उससे पूछता हूं, 'यह क्या? इस विराट अस्तित्व में आप मात्र आधा दर्जन चीजें ही पसंद करते हैं और इससे आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं? इसकी कहां संभावना है?'

जैसे ही आप अच्छे या बुरे का सृजन करते हैं, आप संसार को विभाजित करते हैं। एक बार जब आप इसे विभाजित कर देते हैं, फिर समाहित करने का प्रश्न ही कहां है? योग का प्रश्न ही कहां है?

जैसे ही आप अच्छे या बुरे का सृजन करते हैं, आप संसार को विभाजित करते हैं। एक बार जब आप इसे विभाजित कर देते हैं, फिर समाहित करने का प्रश्न ही कहां है? योग का प्रश्न ही कहां है? सत्य को जानने का कहां प्रश्न है? अच्छा और बुरा हमेशा आपके अहं की मांग के अनुसार होता है। अगर आप इसके अनुसार चलते हैं, आप स्वयं को जीवन के द्वंद्व व दोहरेपन का दास बना लेते हैं; आप अस्तित्व को विभाजित कर देते हैं। तब आध्यात्मिक होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति



हम एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं, मगर हम दुश्मन नहीं हैं। हम पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सहकर्मी हैं, नागरिक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात- हम सब अमेरिकी हैं। हमें एक साथ खड़े होना चाहिए।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 18 जुलाई, 1949

शरणार्थियों को कृषि भूमि

जालंधर, १७ जुलाई। पुनर्स्संस्थापन विभाग के डायरेक्टर-जनरल सरदार त्रिलोक सिंह ने आज रात अपने एक ब्राडकास्ट भाषण में बताया कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये ४,८९,६११ हिन्दू-सिख शरणार्थियों में से २५ हजार व्यक्तियों को पूर्वी पंजाब प्रांत तथा पटियाला राज्य संघ में २५ जुलाई को कृषि के लिए जमीनें निर्धारित की जायेंगी। उन्होंने आगे बताया कि ५० हजार शरणार्थियों को उक्त तारीख के बाद आने वाले सप्ताह में जमीनें निर्धारित की जायेंगी तथा उसके बाद के सप्ताहों में व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी। पूर्वी पंजाब प्रांत तथा पटियाला राज्य संघ के माल तथा पुनर्स्संस्थापन विभागों के कर्मचारी भूमि-निर्धारण आज्ञाओं के विवरण तैयार करने में जालंधर के भूमि निर्धारण शिविर में व्यस्त हैं। सरदार त्रिलोक सिंह ने बताया कि शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान में ६७ लाख तीन हजार एकड़ जमीन छोड़कर आये हैं। उन्हें पूर्वी पंजाब में ४७ लाख ३८ हजार एकड़ भूमि निर्धारित की जायेगी। सरकार की इच्छा है कि जिन शरणार्थियों के पास थोड़ी भूमि थी, उन्हें उसका पूर्ण भाग निर्धारित किया जाये। परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका है। जमीन के ८० प्रतिशत दावेदारों के पास १० एकड़ से कम तथा ९६ प्रतिशत दावेदारों के पास ३० एकड़ से कम भूमि थी। एक प्रतिशत से कम व्यक्तियों के पास ६० एकड़ से अधिक जमीन थी। कम भूमि के दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण भूमि की कमी को उन सबमें बांटना अनिवार्य है। इस कारण छोटे दावेदारों की जमीनों को कम न करने की बात असम्भव हो गई। परन्तु इस कटौती को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया गया है।

पटियाला में बाढ़ की स्थिति- पटियाला, १७ जुलाई। पटियाला नगर में और उसके चारों ओर बाढ़ का पानी बहुत उतर गया है। बाजारों में सड़कें दिखाई देने लगी हैं। जो लोग सरकारी इमारतों और कैम्पों में शरण लिये हुए थे, वे अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला (तब मुख्यमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था) अब उन देहातों इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिन्हें हाल में ही भारी वर्षा और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने सारे डिप्टी कमिश्नरों को यह तार दिया है कि वे शीघ्र ही इस बात की सूचना दें कि बाढ़ के कारण कहां और कितनी क्षति हुई है।

गरीब यात्रियों के लिए अहितकारी फैसला

देश के गरीब लोगों को यदि दूर-दराज की यात्रा करनी हो, तो आज भी भारतीय रेल ही उनके लिए सबसे किफायती साधन है। इस बात को सरकारें बखूबी समझती रही हैं और यही कारण है कि यात्री किराये में बढ़ोतरी करने के बजाय वे माल भाड़े में वृद्धि या रेल-भूमि के व्यावसायिक दोहन जैसे उपायों से राजस्व जुटाने की कोशिश करती रही हैं। हालांकि, पिछले अनेक वर्षों से भारतीय रेलवे के बारे में यही कहा जाता रहा है कि वह घाटे में चल रहा है। लेकिन मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि यदि यह बहुत घाटे में चलता रहा, तो फिर इसका इतना विकास कैसे होता गया? यदि सरकार इसके घाटे की भरपायी करती रही है, तो क्या वे एक लोक-कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को ही पूरा नहीं करती रही हैं? मगर आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकारी निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वह आज कहां तक पहुंच गई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपकर सरकारें अपने दायित्वों से छुटकारा पाने लगी हैं।

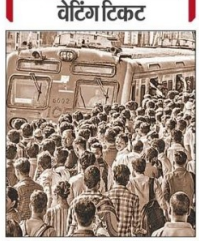
अब रेलवे को भी पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी हो रही है। कोविड महामारी के बाद से भारतीय रेलवे आहिस्ता-आहिस्ता कई सुविधाएं लोगों से छीन चुका है। इस आपदा की आड़ में उसने कई यात्री गाड़ियां हमेशा के लिए बंद कर दी हैं। रियायती दर पर बच्चों को सीटें आवंटित करने की सुविधा हो या बुजुर्गों को मिलने वाली रियायतें, सब छीनी जा चुकी हैं। प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम अनाप-शनाप बढ़ाए गए हैं। अब 1 जुलाई से लागू नए नियम के मुताबिक, यदि वेटिंग टिकट लेकर कोई यात्रा करता है, तो यह गैर-कानूनी है और टिकट परीक्षक ऐसे यात्रियों से 440 रुपये जुर्माना भी वसूल सकता है और अगले स्टेशन पर उतार सकता है या फिर उन्हें जनरल डिब्बे में भेज सकता है।

इस देश में रेल गाड़ियां कितनी कम पड़ती हैं, यह किसी भी पर्व-त्योहार पर बहुत आसानी से दिख जाता है। ऐसे में, रेलवे के नए नियम गरीब मुसाफिरों पर दोहरी मार हैं। एक तो पहले के मुकाबले महंगे दाम पर वे टिकट भी लेते हैं और ट्रेन के अंदर भी अतिरिक्त जुर्माना भरें। इसके बाद भी टीटी के रहमोकरम पर है कि वह बीच सफर में उन्हें ट्रेन से उतार दे या फिर जनरल डिब्बे में जाने को बाध्य करे। यह तो गरीब रेल यात्रियों के साथ सरासर अन्याय है। सरकार पहले उनके लिए सिर्फ स्लीपर व जनरल डिब्बों वाली अधिक ट्रेनें चलाए, फिर ऐसे तुगलकी नियम लागू करे।

रामप्रीत राय, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

वेटिंग टिकट



मुसाफिरों के साथ अब सचमुच न्याय होगा

भारतीय रेल हिन्दुस्तान की लाइफ-लाइन है। करोड़ों लोग इससे रोजाना सफर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दैनिक मुसाफिरों के लिए सीमित दूरी की सिटी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जिनके सहारे लाखों लोग सस्ते दाम के टिकट पर या मासिक पास पर रोजाना अपने काम पर आते-जाते हैं। इन ट्रेनों का समय दफ्तरों के हिसाब से ही रखा गया है। मगर ऐसा अक्सर देखा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में भी दैनिक यात्री न सिर्फ घुस जाते हैं, बल्कि आरक्षित डिब्बों के यात्रियों के साथ कई बार अभद्रता भी करते हैं। ऐसे में, नए नियम से उन मुसाफिरों के साथ न्याय होगा, जो चार महीने पहले से टिकट आरक्षित कराते हैं या तत्काल में अधिक कीमत चुकाकर टिकट लेते हैं और भारी भीड़ के कारण अपने डिब्बे के शौचालय तक नहीं जा पाते।

निस्संदेह, जो वेटिंग टिकट लेकर सफर करते हैं, वे कोई शौकिया ऐसा नहीं करते। सच तो यह है कि उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। उनके पैसे भी लगते हैं, सीट भी नहीं मिलती, आरक्षित सीट वाले यात्रियों की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है, बल्कि कई बार टीटी भी उनके साथ उलझ पड़ते हैं और उन्हें अपमानित कर डालते हैं। ऐसे में, एक बार यदि ये नियम सख्ती से लागू हो गए कि बिना आरक्षण के कोई भी आरक्षित डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, तो यकीनन वे अपनी यात्रा मुल्तवी करने या अन्य वैकल्पिक साधनों पर गौर करेंगे।

इस बात में कोई दोराय नहीं कि भारतीय रेलवे पर यात्रियों का बहुत अधिक दबाव है, लेकिन इतना ही बड़ा सच यह भी है कि बिना अनुशासन के वह अपनी छवि नहीं सुधार सकता। एक तो अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रेन के भीतर की साफ-सफाई प्रभावित होती है, दूसरी तरफ, मुसाफिरों में असंतोष बढ़ता है। लेकिन इसमें सारा दोष रेलवे का है। वह सिर्फ टिकट से पैसे बनाने में जुटा है। आखिर वह इतने वेटिंग टिकट काटता ही क्यों है, जब सीटें सीमित होती हैं? फिर इतने दिनों तक यात्रियों के पैसे अपने पास रखने के बाद क्या वह टिकट कैंसिल करने पर लोगों को उनके पैसों पर ब्याज देता है? उल्टे वह कैंसिल करने पर अब अधिक पैसे काटने लगा है। इसलिए सबसे पहले रेल प्रबंधन को अपने गिरेबान में झांकना होगा। उसको एक अनुशासित तंत्र के रूप में कार्य करना है, तो उसे पहले अपनी कमियों को दुरुस्त करना होगा। अब तकनीक के मामले में वह दुनिया की उन्नत व्यवस्थाओं से टक्कर ले रहा है, तो फिर रेल टिकटों के प्रबंधन में भी यह तार्किकता क्यों नहीं दिखती?

देविका सिंह रावत, टिप्पणीकार

भविष्य में अनपढ़ वह नहीं होगा जो पढ़ न पाए, बल्कि अनपढ़ वह होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है।

- अल्विन टोफ्लर

खाद्य महंगाई की बढ़ती चुनौतियां

मई में खुदरा महंगाई दर 4.75 फीसद के साथ पिछले बारह माह के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69 फीसद थी। प्रमुख रूप से अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ऊंची है।

जयंतीलाल भंडारी

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08 फीसद हो गई है। यह पिछले चार महीनों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर है। चिंताजनक है कि खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 9.36 फीसद रही है। खासकर बाजारों में गेहूं और दाल के बाद आलू, प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर दबाव बढ़ा है। जून 2024 के एक महीने में आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों में क्रमशः 25, 53 और 70 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। 'क्रिसिल मार्केट इंटेलीजेंस एंड एनालिसिस' की मासिक 'रोटी राइस रेट' रपट के मुताबिक शाकाहारी थाली का मूल्य जून 2024 में दस फीसद बढ़कर 29.4 रुपए हो गया है, जबकि यह जून 2023 में 26.7 रुपए था। शाकाहारी थाली का मूल्य मई में 27.8 रुपए था।

शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जी (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद शामिल होते हैं। हालांकि किसानों को आलू, प्याज और टमाटर की अच्छी कीमत दिलवाने के साथ इन वस्तुओं की एक 'वैल्यू चेन' स्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। हर साल जून से अगस्त के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। इस वर्ष मई में खुदरा महंगाई दर 4.75 फीसद के साथ पिछले बारह माह के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69 फीसद थी। प्रमुख रूप से अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ऊंची है। यानी खाद्य वस्तुओं की महंगाई में कमी आने से खुदरा महंगाई दर कम हो सकेगी तथा आम आदमी को राहत मिल सकेगी।

अब मानसून की व्यापक बारिश हो रही है, इससे देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। इससे कृषि विकास के साथ खाद्य महंगाई को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मौसम एजेंसी 'स्काईमेट' और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा है कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून के अच्छा रहने से कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ेगी। स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुसंधान विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहने से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी आपूर्ति बढ़ने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ेगी। दरअसल, बेहतर मानसून से ग्रामीण भारत में कृषि विकास, उद्योग-कारोबार में बढ़ोतरी, छोटे किसानों-मजदूरों, ग्रामीण भारत और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उम्मीदें बढ़ी हैं।

सरकार को ध्यान देना होगा कि जहां वित्तवर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसद रही, वहीं कृषि विकास दर महज 1.4 फीसद थी। पिछले वर्ष 32.8 करोड़ टन उत्पादित खाद्यान्न इसके पूर्ववर्ती वर्ष के 32.9 करोड़ टन से कम है। इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी का अनुमान है। पिछले एक वर्ष में गेहूं की कीमतें 8-10 फीसद बढ़ी हैं। अप्रैल 2024 में देश के गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 75 लाख टन रह गया, जो पिछले सोलह वर्ष में भंडारण का सबसे निचला स्तर है। सरकार 1 जून, 2024 तक करीब 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है। लक्ष्य 372 लाख टन खरीद का है।



इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति शृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। हालांकि इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नियंत्रित है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र महंगाई दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगने की संभावना बन सकती है।

इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति शृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। हालांकि इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नियंत्रित है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र महंगाई दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगने की संभावना बन सकती है।

निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय को कृषि उपज की बर्बादी रोकने के लिए बहुआयामी प्रयासों से ग्रामीण भारत की जरूरतों को खुशियों में बदलने की दिशा में काम करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 15 फीसद खाद्य उत्पादन नष्ट हो जाता है। स्थिति यह है कि लगभग 15 फीसद फल और सब्जियां उपज के बाद ही बर्बाद हो जाती हैं। कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार से कृषि उपज बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है। देश में अधिक शीत भंडार गृह और प्रशीतन सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ना होगा। चूंकि देश में ज्यादातर किसान गरीब वर्ग के हैं और उनके पास छोटी, बिखरी हुई जोत है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वे स्वयं भंडारण ढांचे में निवेश कर सकें।

देश के करीब 92 फीसद शीत भंडार गृहों का संचालन और स्वामित्व निजी क्षेत्र में है, जिनमें छोटे किसानों की सीमित मात्रा की कृषि फसलों का भंडारण महंगा भी होता है। इसलिए खाद्य भंडारण ढांचे में कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के अधिक दखल और अधिक सबसिडी सहयोग की जरूरत है। जहां एक ओर देश में मौजूदा शीत भंडार गृह क्षमता के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा शीत भंडार गृह इकाइयों का भौगोलिक इलाकों के हिसाब से वितरण भी असमान है। गौरतलब है कि भारत में कुल सड़क विस्तार का करीब 30 फीसद हिस्सा अब भी कच्चा है, जिससे कृषि पैदावार को मंडियों तक ले जाने में काफी समय लगता है और इससे भी कुछ पैदावार खराब हो जाती है, जिसका असर कृषि उपजों की कीमतों पर पड़ता है।

जरूरी है कि सरकार खाद्य फसलों की बर्बादी से बचाने और किसानों को उनकी फसल के लाभप्रद मूल्य की प्राप्ति हेतु 24 फरवरी 2024 से प्रायोगिक रूप से शुरू की गई सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से काम करे। इसके तहत देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले पांच वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करके ग्रामीण भारत में अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे।

उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाई जाने, ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने, कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में क्षमता सुधार जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला में सुधार से खाद्य फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगी।

विषमता की बुनियाद

महंगाई का सीधा असर आम उपभोक्ता के घरेलू खर्चों पर पड़ता है। इसलिए यह हैरानी का विषय नहीं कि थोक और खुदरा महंगाई की बढ़ी दरों के साथ ही उपभोक्ता व्यय के आंकड़े भी बढ़े हुए आए हैं। सरकार द्वारा जारी 2022-2023 की घरेलू खर्च रपट के मुताबिक देश के करीब आधे लोगों को तीन वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के बीच यह अंतर बहुत मामूली है। करीब आधी आबादी नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन नियमित नहीं कर पाती। इसकी वजह केवल बढ़ी हुई महंगाई नहीं, बल्कि आय में बढ़ती विषमता है। देश के शीर्ष पांच फीसद अमीर और पांच फीसद सबसे अमीर लोगों के घरेलू खर्च में करीब बीस गुना का अंतर है। पांच फीसद सबसे गरीब ग्रामीण लोगों का औसत घरेलू खर्च 1373 रुपए और पांच फीसद शीर्ष शहरी अमीरों का घरेलू खर्च 20824 रुपए है। इसे लेकर स्वाभाविक ही विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने पिछले दस वर्षों में बढ़ी हुई आय संबंधी विषमता का आंकड़ा पेश करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है।

घरेलू खर्च में बढ़ोतरी और गरीब तथा अमीर के उपभोग व्यय में भारी अंतर आर्थिक विसंगतियों को रेखांकित करता है। महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ने से लोगों को तब परेशानी नहीं होती, जब उसी अनुपात में उनकी आमदनी बढ़ी हो। मगर पिछले पांच-सात सालों में लोगों की क्रयशक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना काल के बाद लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार छिन गए, जिससे उन्हें घर का खर्च चलाना मुश्किल है। तिस पर बढ़ती महंगाई मुसीबतों का पहाड़ बन कर टूटती है। दूसरी तरफ, अमीर लोगों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है। यानी उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। इससे बाजार में भी विसंगतियां पैदा होती हैं। केवल अमीर लोगों के बल पर कोई बाजार नहीं टिक पाता। अमीरों की आमदनी बढ़ने से ऐशो-आराम की वस्तुओं की बिक्री जरूर बढ़ जाती है, मगर आम उपभोक्ता के बल पर खड़े खुदरा बाजार को निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में सृजित कुल संपत्ति का करीब चालीस फीसद हिस्सा देश के केवल एक फीसद लोगों के पास गया है। देश की सत्तर करोड़ आबादी की कुल संपत्ति के बराबर हिस्सा कुल इक्कीस अमीरों के पास है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मगर सरकार इस विसंगति को दूर करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आती।

विचित्र है कि एक तरफ तो देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया जाता है। कुछ वर्षों में देश के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा किया जा रहा है। इसके विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मगर इसके बरक्स दूसरी तस्वीर यह है कि देश की आधी आबादी तीन वक्त का भोजन नहीं जुटा पाती। सरकार खुद इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित करती है कि वह अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। जब तक लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ती और आय की असमानता दूर नहीं होती, तब तक संतुलित आर्थिक विकास की उम्मीद करना मुश्किल बना रहता है। इसके लिए नए रोजगार सृजित करने और वेतन-भत्तों के मामले में व्यावहारिक नीति बनाने की जरूरत होती है, जिसका अभाव लंबे समय से देखा जा रहा है।

मौसम का कहर

देश के कई इलाकों में इन दिनों लोगों को भारी बरसात की वजह से बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ी पड़ रही है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में मानसून के बादल बरसने में संकोच कर रहे हैं। नतीजतन, उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौसम प्रणाली में इस कदर असंतुलन क्यों पैदा हो रहा है? भारतीय मौसम विभाग की ताजा रपट में कहा गया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में इस वर्ष जून का महीना 31.73 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के साथ वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा है। इस बीच, दिल्ली में मई से जून के बीच बत्तीस दिन ऐसे रहे, जब तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इसके बाद दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही चौबीस घंटों में इतना पानी बरसा कि अट्ठासी वर्षों का रेकार्ड टूट गया। उसके बाद हल्की बारिश ही हो रही है, जिससे उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और मैदानी क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे पिछले दो-तीन सप्ताह में कई लोगों की जान जा चुकी है।

मौसम के इस बदलते मिजाज के पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण माना जाता है। यूनिवर्सिटी आफ टेक्सास की ताजा रपट के मुताबिक, मौसम में आ रहे बदलाव जलवायु परिवर्तन के खतरों का संकेत हैं। बढ़ती वैश्विक तपिश से भविष्य में और भी भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में तेजी से हो रहे बदलावों के पीछे कार्बन उत्सर्जन का बड़ा योगदान है। दरअसल, पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी बढ़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम पर पड़ रहा है। हवा में बढ़ते 'एयरोसोल सल्फेट' की मात्रा भी धरती का तापमान बढ़ा रही है, जिससे अरब और हिंद महासागर का तापमान बढ़ रहा है और इससे मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया भर में हो रहे प्रयासों को गति देने की जरूरत है। तभी मौसम में हो रहे असामान्य बदलावों का असर कम हो पाएगा।

विरोध का विवेक

महेश परिमल

हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं, जो सदैव नकारात्मकता फैलाने में लगे होते हैं। उनकी दृष्टि में केवल वे खुद सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। वास्तव में जो विरोध करते हैं, वे गलत नहीं होते, बल्कि वे अलग होते हैं। जो अलग होते हैं, वही कुछ ऐसा करते हैं, जो अब तक नहीं हुआ होता है। इस उक्ति को अगर विस्तार दिया जाए, तो यह हमारे सामने एक नई इबारत के रूप में पेश होगी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विरोध की भावना होती है। कुछ इसे व्यक्त करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ अपनी इस भावना को विरोध में बदलकर सभी का अहित करते रहते हैं, तो कुछ के विरोध विद्रोह के रूप में हमारे सामने आते हैं।

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे भी पल आते रहते हैं जब हमें गलत साबित कर दिया जाता है। हम लाख समझाते हैं कि हम कतई गलत नहीं हैं, बस हमारी सोच कुछ अलग है, इसलिए हमारा काम आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको हमारा काम हमारे न रहने पर समझ में आए, लेकिन भीड़ उनकी बात नहीं मानती। वह अपना गुस्सा उस तथाकथित गलत व्यक्ति पर उतारती है। इससे वह व्यक्ति या तो मारा जाता है या फिर वहां से निकाल दिया जाता है। बरसों बाद उस व्यक्ति की बात सच साबित होती है, तो उसकी बात को तब सुनने वालों को निराशा होती है। उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता।

इसलिए जब भी कहीं किसी का विरोध हो रहा हो, तो उस विरोध करने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। पूरी भीड़ एक तरफ ही होगी। यह भी सच है कि भीड़ के पास विवेक या बुद्धि नहीं होती। भीड़ का केवल आक्रामक होना यह दर्शाता है कि उसमें शामिल लोगों की बुद्धि भी काम करना बंद कर चुकी है। अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस तरह की भीड़ विनाश को आमंत्रित करती है और अपना ही नुकसान करती है। विरोध करने वाले का साथ बहुत कम लोग देते हैं। कई बार तो विरोधी अकेला ही खड़ा होता है।

विरोध की आवाज को अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता। विरोध की आवाज में इतना दम होता है कि जब वह आती है, तो एक विस्फोट के रूप में आती है। अपनी स्थिति को समझने के लिए राजा-महाराजा पहले रात में आम आदमी की तरह वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे। विरोध करने वाला हर बार गलत नहीं होता, वह अलग होता है। कई बार वह दूरदर्शी होता है। ऐसे लोगों को समय की पदचाप को पहचानना आता है। इसीलिए वह कुछ अलग सोचता है। वह भीड़ से अलग होता है। विरोध करने के पहले वह धीमे से सामने वाले को समझाने की कोशिश भी करता है। कोशिशें नाकाम होने के बाद ही वह विरोध का परचम उठाता है। विरोध को चौना करने के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। कई बार ये कोशिशें कामयाब भी होती हैं। पर विवेक पर आधारित विरोध तो विरोध होता है। वह किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाता है। ऐसा एक विरोधी जब खत्म होता है, तो वह अपने विचारों की झोली कहीं छोड़ देता है। यह झोली भीड़ में ही किसी के हाथ लग जाती है। धीरे-धीरे झोली के विचार पुष्पित और पल्लवित होने लगते हैं।

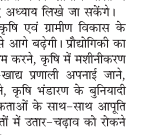
कई लोग असहमति और विवेक पर आधारित विरोध को जानते-बूझते हुए भी अनदेखा करते हैं। ऐसे विरोध में संभवतः सबका हित छिपा होता है। अगर अकेले का हित किसी विरोध की जड़ में है, तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहता, क्योंकि इसमें स्वार्थ के तत्त्व होते हैं। जिस विरोध में सबका हित हो, वही विरोध अधिक समय तक जीवित रहता है। विरोध में सद्विचार होता है। इसे समझने के लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। विरोध ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी का हित हो, मगर जरा भी नुकसान न हो। जापान में जूते की एक कंपनी के कर्मचारियों को विरोध जताना था, तो सबने यह फैसला किया कि वे सब केवल एक ही जूता बनाएंगे, इससे कंपनी को नुकसान नहीं होगा। जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तब तक वे एक ही पांव का जूता बनाते रहेंगे। इससे कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम उठाया। विरोध में अहित न हो, इसका पूरा खयाल रखा जाए, तो ऐसे विरोध का बहुत से लोग समर्थन करेंगे। जो नहीं करेंगे, उनका पर्दाफाश हो जाएगा।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा एक हाथ अगर विरोध के लिए उठ रहा है, तो दूसरा हाथ किसी के सिर पर संरक्षण के रूप में होना चाहिए। ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं कि अपने आग्रहों की वजह से कुछ लोग किसी बात का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह संभव है कि वह बात व्यापक जनहित में कही जा रही हो। यह भी संभव है कि उस बात या पहल में उस व्यक्ति का भी हित शामिल हो, जो महज विरोध के लिए विरोध करता है। इसलिए विरोध तभी सार्थक है, जब उसका आधार विवेक पर टिका हो।

दुनिया मेरे आगे

भी इ के पास विवेक या बुद्धि नहीं होती। भीड़ का केवल आक्रामक होना यह दर्शाता है कि उसमें शामिल लोगों की बुद्धि भी काम करना बंद कर चुकी है। अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस तरह की भीड़ विनाश को आमंत्रित करती है और अपना ही नुकसान करती है।

महंगी थाली



बारिश न हो तो सूखे के कारण सब्जियों के दाम में वृद्धि हो जाती है और अगर बारिश हो जाए तो भी सब्जियों के खराब होने के कारण दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए, यह शायद कोई नहीं सोचता है। देश में उगाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखकर यह लगता है कि यह कहीं दूर विदेशों से आई है। देश के कुछ राज्यों में आजकल टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा, कभी प्याज तो कभी अन्य सब्जियों के मूल्य बेलगाम हो जाते हैं। कृषिप्रधान देश में सब्जियों की कीमत में इस कदर बढ़ोतरी और किसानों की दयनीय दशा सचमुच अफसोसनाक है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए सरकारें बहुत से तर्क दे सकती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, उनमें मुख्य रूप से इनके भंडारण के लिए सरकार द्वारा उचित प्रबंध न होना भी है। यह भी हो सकता है कि किसानों ने सब्जियों की पैदावार इसलिए भी कम करना शुरू कर दिया हो कि अगर सब्जियों की समय पर बिक्री न हुई तो ये सड़ जाएंगी और उन्हें भारी नुकसान होगा। सब्जियों के बढ़ते दाम के लिए सरकार की जो गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, उनमें तो सुधार किया ही जा सकता है।

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

कारोबार का पाठ

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और कराने वाले कोचिंग संस्थान, दोनों की भरमार है। कोई भी विद्यार्थी किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने जाता है तो वे संस्थान उसे यह नहीं बताते कि वह परीक्षा की तैयारी करने योग्य है या नहीं। यह शायद व्यापार सिद्धांत है कोचिंग संस्थानों का और जो विद्यार्थी और उनके अभिभावक हैं, उनका मूल मकसद है प्रतियोगी परीक्षाओं में हर हाल में सफलता पाना। छोटा बच्चा हर खिलौने की तरफ आकर्षित होता है। वही छोटा बच्चा जब बड़ा होता है और उसे अगर नहीं समझाया जाएगा तो हर चीज की तरफ यह आकर्षित होगा, बिना समझे। यही बात कोचिंग संस्थानों और विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। निश्चित रूप से बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे संस्थान केवल अपने व्यापार को ही बढ़ाने में लगे हैं।

- वेद सिंह यादव, लखनऊ

सुरक्षित खाद्य

अच्छा खानपान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी क्रम में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नए नियमों के मुताबिक खाद्य कंपनियों को अब खाने के डिब्बे पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में पोषक तत्त्वों की जानकारी देनी होगी। इसे सरहनीय पहल कहा जा सकता है। उपभोक्ताओं को मालूम भी नहीं रहता कि वे जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, उसमें किस पदार्थ की कितनी मात्रा है। अगर कुछ हद तक जानकारी होती भी है तो कहीं बारीक या छोटे अक्षरों में लिखा होता है, जिससे पढ़ने में असुविधा होती है। स्पष्ट लेखन से उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी मिलेगी। व्यक्ति रोगी हो तो उसे यह निर्णय लेने में सुविधा होगी कि वह उसका सेवन करे या न करे। इसका उद्देश्य ग्राहकों को किसी उत्पाद में पोषक तत्त्वों की जानकारी मुहैया कराना और बेहतर समझ पर सेहत से जुड़े फैसले लेने में मदद करना है।

- योगेश जोशी, बड़वाह

जागरूकता की जरूरत

हाथरस में एक बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ की घटना ने यह साबित कर दिया है कि हमारी कानून व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता दोनों में ही गंभीर खामियां हैं। महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी कमजोर है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में न्याय और समानता की भावना मजबूत हो। हमारे बच्चों को न केवल शिक्षा, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस घटना से हमें सीख लेते हुए अपने समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस न करे।

- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 18 जुलाई 2024

बिछने लगी बिसात

महाराष्ट्र में अजित पवार की अगुआई वाली NCP से चार नेताओं के इस्तीफे को अगर पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है तो यह बेवजह नहीं है। हालांकि पहली नजर में यह प्रदेश के एक खास क्षेत्र पिंपरी चिंचवड़ से जुड़े नेताओं का असंतोष लगता है लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।

फैसले की टाइमिंग | चारों नेताओं का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब पहले से ही राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा चल रही है कि अजित पवार की अगुआई वाले धड़े से कई नेता शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दो दिन पहले इसी पार्टी के एक प्रमुख नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात करके सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में भुजबल ने इसे OBC आरक्षण के मसले पर की गई मुलाकात बताया और कहा कि इसका कोई और मतलब न निकाला जाए।



NCP: इस्तीफों से अनिश्चितता

कमजोर प्रदर्शन | 2023 में शरद पवार की अगुआई वाली NCP से अलग होकर अजित पवार धड़ा प्रदेश की महायुति सरकार में शामिल हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के समर्थन का दावा किया जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में शरद पवार को 8 सीटें मिलीं जबकि अजित पवार को मात्र एक सीट। इसके बाद कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में अजित पवार धड़े के संभावित प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

गठबंधन में असहजता | दिलचस्प है कि राज्य की महायुति के तीनों धड़ों- BJP, शिवसेना (शिंदे) और NCP (अजित पवार)- में सबसे कमजोर कड़ी NCP को ही माना जाता है। मामला सिर्फ लोकसभा में जीती सीटों का नहीं है। शिवसेना और BJP के साथ को आज भी सहज बताया जाता है, लेकिन NCP को मिसफिट कहा जाता है। संघ के हलकों में भी कहा जाता है कि NCP से हाथ मिलाने से कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला है। पिंपरी चिंचवड़ में हुए इस्तीफों के पीछे जिस असेंबली सीट के टिकट को विवाद की जड़ बताया जा रहा है, वह सीट BJP के हिस्से की है। जाहिर है, अजित पवार चाहकर भी अपने करीबी नेता की मांग पूरी नहीं कर सकते थे।

आवाजाही बढ़ने के आसार | हालांकि ऐसी मजबूरियां सिर्फ अजित पवार के हिस्से में नहीं हैं। एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना के सामने भी किसी न किसी रूप में ये चुनौतियां आएंगी। विपक्षी खेमा भी इनसे पूरी तरह अछूता रह पाएगा, ऐसा लगता नहीं है। तीन के बदले पांच पार्टियों का वजूद आगामी विधानसभा चुनावों को अतीत के तमाम चुनावों से अलग रंग दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आने तक किन दलों में किस तरह की आवाजाही होती है।

साड्डी दिल्ली

जेंटलमैन प्लेयर

विवेक शुक्ला

तुलसी दुरेजा 76 साल की उम्र में भी बैडमिंटन कोर्ट में जीतने के लिए उतरते हैं। उन्होंने 1962 में पहली बार अपने लाजपत नगर के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। तब वह 14 साल के थे। उसके तुरंत बाद वह दिल्ली की सब जूनियर बैडमिंटन टीम के मेंबर बन गए। उन्होंने इस दौरान ना जाने कितनी प्रतियोगिताएं जीतीं। बीते दिनों त्यागराज स्टेडियम में आयोजित दिल्ली स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में तुलसी दुरेजा ने दिवाकर जोशी के साथ 70+ उम्र कैटिगरी में डबल्स का खिताब जीता।



Subrata Dhar

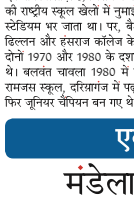
अपनी खिताबी जीत से ज्यादा तुलसी दुरेजा इस बात से खुश हैं कि उनके पुराने दोस्त प्रकाश पादुकोण पेरिस ओलिंपिक खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम के मेंटर होंगे। दुरेजा कहते हैं, प्रकाश जेंटलमैन प्लेयर रहे। जब 1982 में यहां एशियाई खेल हुए तो प्रकाश पादुकोण भारतीय टीम के नॉन प्लेइंग कैप्टन थे। वह जब भारतीय टीम के साथ मॉडर्न स्कूल के शंकर लाल हॉल में प्रैक्टिस करने आते, तो अन्य देशों के खिलाड़ी भी उन्हें देखने के लिए अपनी प्रैक्टिस रोक देते। प्रकाश पादुकोण ने तालकटोरा स्टेडियम में मरहूम सैयद मोदी, उदय पवार आदि के साथ कई यादगार मैच खेले। प्रकाश पादुकोण और तुलसी दुरेजा आधी सदी पुराने दोस्त हैं। वह दुरेजा से दिल्ली बैडमिंटन का हालचाल लेते रहते हैं। दुरेजा दिल्ली बैडमिंटन की प्राण और आत्मा हैं। वह दिल्ली से 1972-83 के बीच खेले। उसके बाद वह 35+,45+ और 55+ कैटिगरी में खेले। उन्हें बैडमिंटन के नियमों की गहरी समझ है। वह एशियाड-82 में चीन और इंडोनेशिया टीम के बीच हुए फाइनल मैच की अंपायरिंग कर रहे थे। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिसने बैडमिंटन, क्रिकेट और वालीबॉल में दिल्ली की राष्ट्रीय स्कूल खेलों में नुमाइंदगी की है। इस दौरान रोज दर्शकों से स्टेडियम भर जाता था। पर, बैडमिंटन के चाहने वालों को मलविंदर ढिल्लन और हंसराज कॉलेज के बलवंत चावला की कमी खलती है। दोनों 1970 और 1980 के दशक में दिल्ली बैडमिंटन के शिखर नाम थे। बलवंत चावला 1980 में दिल्ली के सिंगल्स चैंपियन बने। वह रामजस स्कूल, दरियागंज में पढ़ते हुए ही दिल्ली के सब जूनियर और फिर जूनियर चैंपियन बन गए थे।

एकदा

मंडेला का झूठ

साल 1952 की बात है। जोहानिसबर्ग में भेदभाव वाले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में तैयार पत्र को सरकार को सौंपना था। इसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. जेम्स मोरोको के हस्ताक्षर की जरूरत थी। वह 120 मील दूर रहते थे। नेल्सन मंडेला के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। रास्ते में उन्हें दो जगहों पर घृणा और अपमान का सामना करना पड़ा। किसी तरह वहां से निकले तो पेट्रोल खत्म हो गया। पैदल चले तो एक फार्म हाउस आया। वहां की मालकिन से पेट्रोल मांगा, उसने मना कर दिया और नफरत भरी नजरों से देखते हुए दरवाजा बंद कर लिया। दो मील चलने के बाद दूसरा फार्म हाउस आया। इस बार अंग्रेजी में झूठ बोले, 'मैं ड्राइवर हूं। मेरे मालिक की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल की कीमत देने के लिए तैयार हूं। क्या पेट्रोल मिलेगा?' इस बार उन्हें पेट्रोल मिल गया। वहां उन्हें नफरत जैसी कोई बात नहीं दिखी। डॉ. मोरोको के हस्ताक्षर के बाद सरकार को ज्ञापन सौंप दिया गया, लेकिन सरकार ने मांगें नहीं मानीं। हड़तालें हुईं, गिरफ्तारियां हुईं, सजा हुई। लंबा वक्त गुजर गया, पर नेल्सन मंडेला को यह बात सताती रही कि वह झूठ नहीं बोलते तब भी उन्हें पेट्रोल मिल जाता। उस महिला में उन्हें घृणा नहीं, प्रेम नजर आया था। नेल्सन का जीवन प्रेम और घृणा से भरा रहा, लेकिन उन्होंने प्रेम का रास्ता चुना। उन्होंने मन, वचन और कर्म से गोरों से घृणा नहीं की क्योंकि उन्हें भी तो कुछ गोरों का प्रेम मिला था। वह कहते थे कि मनुष्य प्रेम और घृणा के साथ पैदा नहीं होता है। सब यहीं सिखाया जाता है, तो प्रेम ही क्यों न सीखें!

संकलन : हरिप्रसाद राय



Subrata Dhar

क्या आरक्षण पर नए सिरे से हो बहस

पिछड़े तबकों के ही वंचित हिस्से का हक़ मार रहा है 'क्रीमी लेयर' समूह



उमेश चतुर्वेदी

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था बनाते वक्त डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 10 साल में यह समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण मिला, उनकी हालत में सुधार हुआ या नहीं। आंबेडकर ने तब यह भी कहा था कि आरक्षण से यदि किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसकी अगली पीढ़ी को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। उनका तर्क था कि आरक्षण बैसाखी नहीं है, जिसके सहारे पूरी जिंदगी काटी जाए। इसी वजह से संविधान में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई।

आरक्षण की उलटबांसी | आरक्षण के समर्थक आंबेडकर की बातों को ब्रह्मसूत्र की तरह स्वीकार तो करते हैं, लेकिन आरक्षण पर उनके विचार से कन्नी काट जाते हैं। यही वजह है कि कोई पूजा खेडकर सामने आ जाती है और आरक्षण के दायरे में ना होने की वैधानिकता के बावजूद आरक्षण के प्रावधान की संकरी गलियों से अपने लिए राह निकाल लेती है। लोक विमर्श में आरक्षण की व्यवस्था उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां चाहते हुए भी कोई राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर सकता।

आरक्षण व्यवस्था के अंतर्विरोध

- लाभ उठा चुके परिवार ही पाते हैं फायदा
- क्रीमी लेयर की सीमा कम करना है जरूरी
- क्रीमी लेयर में वेतन की आय नहीं जोड़ी जाती

आरक्षण विरोधी नाकाम रहे | मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में लागू किए जाने के बाद आरक्षण के खिलाफ देश में आंदोलन तो खूब हुए, लेकिन वे नाकाम रहे। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू हो गई। यह आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में नहीं था। वीपी सिंह ने नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दिया तो 2004 में मानव संसाधन मंत्री बने अर्जुन सिंह ने शैक्षिक संस्थानों के दाखिलों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का फैसला किया। इसके खिलाफ सात 2006 में छात्रों के एक समूह ने 'यथ फॉर इक्वलिटी' नाम का ग्रुप बनाकर आंदोलन छेड़ा। लेकिन वे भी नाकाम रहे।

क्रीमी लेयर की सीमा | आरक्षण प्राप्त कर चुके परिवारों की अगली पीढ़ी को आरक्षण न देने का विचार आगे बढ़ा, 'क्रीमी लेयर' शब्द का उदय हुआ। क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई, तब एक लाख रुपये सालाना से ज्यादा आय वाले लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया। आय की इस सीमा को साल 2004 में बढ़ाकर ढाई लाख और 2008 में साढ़े चार लाख रुपये सालाना किया गया। आरक्षण की मांग बढ़ती रही और सरकारें सियासी दबाव के आगे झुकते हुए इस सीमा को बढ़ाती रहीं। क्रीमी लेयर सीमा साल 2013 में छह लाख और 2017 में आठ लाख रुपये सालाना कर दी गई।

वेतन शामिल नहीं | यहां एक तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्रीमी लेयर में वेतन वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। हालांकि 1993 में जब इसके लिए नियम बनाए गए थे, तो क्रीमी लेयर में कृषि आय के साथ वेतन को भी जोड़ा गया था। इसका पिछड़े वर्ग की ओर से विरोध हुआ तो सियासी दबाव में वेतन को छोड़ दिया गया। साल 2020 में जब मौजूदा केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो उसमें वेतन की आय को भी जोड़े जाने का सुझाव दिया गया जिसका BJP के पिछड़े वर्ग के सांसदों तक ने खुला विरोध किया।

पिछड़े ही वंचित हो जाते हैं | सवाल है कि अगर पिछड़े वर्गों की ही बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं, जिन्हें कृषि या दूसरे स्रोतों से बड़ी आय होती है। यह भी सच है कि प्रतिभा और आरक्षण के दम पर एक पूरी पीढ़ी ऐसी नौकरियों में आ चुकी है, जो उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। वेतन वाले तबके को किनारे रखने की वजह से पिछड़ों के लिए मिलने वाले आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्ग के ही लाखों-करोड़ों बच्चों को नहीं मिल पाता।

आरक्षण की जरूरत किसे | आंबेडकर के ही शब्द उधार लें तो आरक्षण की जरूरत पिछड़े वर्ग के उन लोगों को है, जो सचमुच पिछड़े हैं। पूजा खेडकर के बारे में जो सूचनाएं सामने आई हैं, उनके अनुसार उनके पिता ने 40 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। सवाल है कि क्या इस आय वर्ग के लोगों को पिछड़ा और आरक्षण के उपयुक्त माना जाना चाहिए?

हर पहलू पर हो बहस | विमर्श इस पर होना चाहिए कि पिछड़ों में ही कितने वाजिब लोगों को उनका आरक्षण का हक मिल रहा है? उनका हक कोई सवर्ण नहीं मार रहा, बल्कि उनके ही तबके के खाए-अघाए लोग मार रहे हैं। जिस तरह के सियासी हालात हैं, उन्हें देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता।

किसे मिले लाभ | आरक्षण की व्यवस्था में कम से कम उन लोगों को तो फायदा मिले, जो सचमुच कमजोर हैं, जिन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत उन लोगों की तुलना में ज्यादा है, जिनके माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं। जो समृद्ध हैं, उन्हें आखिर आरक्षण मिलना ही क्यों चाहिए? सवाल यह भी उठना चाहिए कि समृद्धि की परिभाषा और दायरा बदला ही क्यों जाए? और अगर बदला जाए उसमें वेतन की आय को क्यों नहीं जोड़ा जाए?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

आमने-सामने

क्रीमी लेयर की आड़ में आरक्षण को कमज़ोर करने की कोशिश ठीक नहीं



अनिल सिन्हा

नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जो कभी भी बड़ी बहस छेड़ देता है। अभी यह मुद्दा विवादों में घिरी महाराष्ट्र की एक IAS अधिकारी के उस सर्टिफिकेट के कारण चर्चा में आया है, जिसमें उन्हें क्रीमी लेयर से बाहर का बताया गया है। यह लेयर पिछड़े वर्ग के उन लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखने के लिए बनाया गया है, जिनके परिवार की सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से ज्यादा है। लेकिन इस महिला अधिकारी का मामला सामने आने से पहले से महाराष्ट्र में मराठों को OBC कोटे के भीतर आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। देश के किसी न किसी हिस्से में आरक्षण का मुद्दा गरमाया ही रहता है।

AI Image



समान अवसर का सिद्धांत | संविधान सभा में आरक्षण पर हुई बहस का जवाब देते हुए बाबा साहेब आंबेडकर ने साफ किया था कि आरक्षण का प्रावधान करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि यह अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन न करे। उनका तर्क था कि नौकरी की ज्यादा सीटें सभी के लिए खुली रख कर अवसर की समानता का पालन हो सकता है। यही वजह है कि 50% से ज्यादा आरक्षण को न्यायपालिका गैर-संवैधानिक करार देती है। निचले पायदान पर खड़े लोगों को ऊंचे पायदान पर खड़े लोगों के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना समान अवसर के सिद्धांत को ही ताकत देता है।

मेरिट के सवाल के पीछे | हालांकि आरक्षण के खिलाफ तर्क देने वाले आज भी अवसर की समानता के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। वे दूसरा सवाल मेरिट का उठाते हैं। पहले आरोप का जवाब संविधान के प्रावधानों से ही मिल जाता है। दूसरे तर्क का उत्तर ढूंढना भी कठिन नहीं है। असल में, मेरिट की बात जाति के आधार पर चले आ रहे सदियों पुराने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ही की जाती है। डोनेशन देकर पढ़ाई करने वालों की मेरिट को लेकर शायद ही इस तरह का संदेह व्यक्त किया जाता है।

सभी तबकों को नुमाइंदगी | संविधान में आरक्षण का प्रावधान नौकरियों और शिक्षा में उन समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जो गैर-बराबरी व भेदभाव के कारण इससे दूर रह गए हैं। आरक्षण जन्म आधारित जाति व्यवस्था को अपना आधार बनाता है, लेकिन उसे खत्म करने में अपनी भूमिका भी निभाता है। देश को संचालित करने वाले पदों पर सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देने से समाज न केवल अधिक लोकतांत्रिक बनता है, बल्कि समाज में समता का रास्ता भी तैयार होता है।

जटिल पहलू | आरक्षण को लेकर होने वाली बहस में क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का मुद्दा काफी चर्चा में रहता है। इसी तरह उन परिवारों को आरक्षण की सुविधा नहीं देने की मांग अक्सर होती रहती है जिनकी एक पीढ़ी को यह सुविधा मिल चुकी है। आरक्षण समर्थक बुद्धिजीवियों का बड़ा तबका भी इन प्रावधानों के पक्ष में है। लेकिन ये सवाल वास्तव में जटिल हैं।

रिजर्वेशन की खूबी-खामी

- सभी को समान रूप से बढ़ने का मौका देता है
- समता की जमीन तैयार करता है
- जाति की जकड़न कम नहीं करता

क्रीमी लेयर की सीमित उपयोगिता : OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को मजबूत करने और आरक्षण पा चुके परिवारों को सुविधा से वंचित करने की मांग इन तबकों के बीच वन रही गैर-बराबरी को दूर करने के उपाय भर हैं। इसे आरक्षण के विरुद्ध सैद्धांतिक हथियार बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

भर्ती तंत्र का पूर्वाग्रह | जिन समूहों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत वास्तव में बेहतर हो चुकी है, उन्हें आरक्षण से बाहर करने की यात सैद्धांतिक रूप में सही है। लेकिन जरूरी ईमानदार व्यवस्था नदारद है। भर्ती करने वाले तंत्र को लेकर यह शिकायत लगातार आ रही है कि 'योग्य उम्मीदवार नहीं मिले' कह कर वह पद खाली छोड़ देता है।

संपूर्ण रोजगार की लड़ाई नहीं | बहस का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या आरक्षण शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल को हल करने में मदद करता है? क्या यह जातिवाद पर निर्णायक चोट करता है? यह वाकई दिलचस्प है कि आरक्षण के समर्थक तथा विरोधी, दोनों ही कभी भी संपूर्ण रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ते। इसी तरह सामाजिक न्याय की राजनीति का अर्थ सिर्फ आरक्षण की मांग रह गया है।

जाति की गोलबंदी | आरक्षण और जाति की गोलबंदी आपस में इस तरह गुंथ गई है कि विरोध करने रहे समूह भी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्हें रोजगार पाने का सबसे आसान रास्ता यही दिखाई देता है। लेकिन आर्थिक नीतियों के कारण रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं। संगठित क्षेत्र सात प्रतिशत से भी कम रोजगार देता है। कुल रोजगार में सरकारी रोजगार का प्रतिशत भी तीन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में, आरक्षण की मांग को लेकर की जा रही जाति आधारित गोलबंदी से रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामाजिक विभाजन जरूर बढ़ेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

तीन राज्य तय करेंगे ट्रंप का फ्यूचर



माइकल वासिस्रा

जानलेवा हमले में बाल-बाल बचने के बमुश्किल 48 घंटे बाद डॉनल्ड ट्रंप ने ओहायो के 39 साल के सीनेटर जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। वेंस ने 2016 में ट्रंप का विरोध किया था और तब उन्हें लिबरल्स से सराहना मिली थी। वही वेंस अब ट्रंप की नीतियों का प्रचार करने के लिए देशभर में घूमेंगे। इसमें इमिग्रेशन को सीमित करने की मांग भी शामिल है। इस दौरान वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी भी होंगी। येल यूनिवर्सिटी से पढ़ीं उषा पेशे से वकील हैं और उनके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ था।

ट्रंप का प्रभाव | रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाने वाला ओहायो ट्रंप के लिए सुरक्षित जगह है। हालांकि सीनेट की दौड़ में यहां कड़ी टक्कर हो सकती है। ऐसे में सीनेट पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए वेंस रिपब्लिकन पार्टी की स्ट्रैटिजी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन, वेंस का चयन दिखाता है कि रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप का असर कितना गहरा हो चुका है।

वेंस की काबिलियत | देखा जाए तो वेंस एक आदर्श ट्रंप रिपब्लिकन हैं। ऐसा शख्स, जो काफाजी वर्ग के श्वेत अमेरिकियों के गुस्से को दिशा दे सकता है। साथ ही, उस वक्त काम आ सकता है, जब ट्रंप को लोगों को एकजुट करने की जरूरत पड़े। इसके अलावा, 'प्रोजेक्ट 2025' के दक्षिणपंथी लक्ष्य हैं, जो ट्रंप की वापसी पर कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं।

जीत पर दांव | हमले से पहले पॉलिटिकल बेटिंग साइट्स ने ट्रंप की जीत की संभावना लगभग 60% रखी थी। हमले के बाद यह आंकड़ा 65% हो गया और तब से यह केवल 67% तक ही पहुंचा है। इस घटनाक्रम से ट्रंप की राजनीतिक संभावनाओं में निश्चित रूप से सुधार हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीत ही जाएंगे।



AI Image

कॉमन रूम

नफरत करने वाले ज्यादा | अधिकांश अमेरिकियों ने बरसों पहले ट्रंप को लेकर अपना मन बना लिया था। उनसे प्यार करने वालों की तुलना में नफरत करने वाले ज्यादा हैं। ट्रंप चाहें कुछ भी करें या कहें, लगभग 40% अमेरिकी उनका समर्थन करते हैं और 50% उनके खिलाफ हैं। 10% अमेरिकी अब भी तय नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि सभी अमेरिकियों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, तो ट्रंप किसी भी आधे सक्षम प्रतिद्वंद्वी से निर्णायक अंतर से हार जाएंगे।

उग्र का फैक्टर | इस समय ट्रंप के विरोधी निराश हैं। कुछ अरसा पहले ही उन्होंने जो बाइडन को टीवी पर डिबेट में संघर्ष करते देखा। बाइडन से डेमोक्रेट्स अपील कर रहे हैं कि वह उम्मीदवारी छोड़ दें। माना जा रहा है कि यह चुनाव बेहद करीबी होगा। ऐसे में बाइडन की उम्र और फिटनेस निर्णायक साबित हो सकती हैं। अगर उनके संभावित 1% वोटर भी मतदान करने नहीं निकले तो ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं।

अब भी समय | चुनाव परिणाम इन तीन राज्यों के रिजल्ट पर निर्भर हो सकता है - मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। ये तीनों ही स्विंग स्टेट हैं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इन राज्यों में ट्रंप के प्रति सहानुभूति थोड़ी बहुत जाएगी। पेंसिल्वेनिया की ट्रिप से पहले ट्रंप को मामूली बढ़त हासिल थी, लेकिन अब वह पूरी तरह फेवरिट बन चुके हैं। हालांकि अमेरिकी राजनीति में चार महीने का समय बहुत होता है। 12 मई को ही सट्टेबाजों ने बाइडन को आगे बताया था।

बदलाव की उम्मीद | पिछले महीने की डिबेट के बाद कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं दिखा। तब कई अमेरिकियों को लगा था कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकतीं। लेकिन, पिछले शनिवार को अमेरिका ने एक नया निचला स्तर देखा। वेशक, चीजें और खराब हो सकती हैं, लेकिन वे सुधर भी सकती हैं। अगर बाइडन को भरोसा हो जाता है कि वह नहीं जीतेंगे तो ट्रंप के मुकाबले कोई युवा उम्मीदवार आ सकता है। वैसे भी डेमोक्रेट्स का सम्मेलन अगस्त आखिर तक नहीं है यानी उनके पास कैंडिडेट बदलने के बाद भी मोमेंटम हासिल करने के लिए वक्त है। जो भी हो, लेकिन इस बदलाव में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की अहम भूमिका होगी।

(लेखक Newsweek और दूसरे अमेरिकी मीडिया संस्थानों के लिए लिखते हैं)

मंज़िल पाने के लिए ऑन करना होगा दिल का GPS

श्री प्रेम रावत जी

इस जीवन का हर पल कीमती है। इस अवसर को गंवाना नहीं है। उस दिशा में चलना है, जिसके बारे में पता हो। एक बार चल पड़े तो पूरे आत्मविश्वास के साथ चलना है। अक्सर ऐसी सलाहें भी दी जाती हैं। लेकिन बताएगा कौन? नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दिशा सूचक यंत्र की जरूरत पड़ती है। आजकल फोन पर लोकेशन डालकर चल पड़ते हैं और गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी लोकेशन बताने वाला यंत्र लगा है, वह है हृदय। यह सटीक है, गलत रास्ता नहीं बताता। यह हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

हममें से कुछ लोग 'Ostrich Syndrome' की तरह हो गए हैं। हम शुतुर्मुर्ग की तरह गड्ढा खोदते हैं और अपना सिर उसमें छिपा लेते हैं। सोचते हैं कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। इस तरह से जीना, कोई जीना नहीं है। जीवन तब है जब हम जीवित होने का आनंद अंदर महसूस करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह यह है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति शांति से रह सकता है। यह प्राथमिक बात है, इसका कोई विकल्प नहीं। हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। ये खोखले शब्द नहीं हैं। यह सच है। अपने हृदय को निर्णायक बनने देना है, क्योंकि यही सबसे नजदीक है। यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है।

जिस बात की यहां चर्चा हो रही है, वह किसी कागज के पन्ने पर लिखने जैसी नहीं। ऐसी भी नहीं है कि बार-बार कहकर इसे समझाया जाए। हृदय-रूपी किताब के पन्ने पर पहले से लिखी हुई है। यह किसी मनुष्य की कृति नहीं है। यह कृति है हमें बनाने वाले की, जिसने सारे संसार की रचना की है। हृदय की इस पुस्तक में लिखा हुआ है, उन समस्याओं को कोई गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, कोई आर्मी या एयरफोर्स हल नहीं कर सकती, कोई वैज्ञानिक हल नहीं कर सकता। वह समस्या है मनुष्य के अंदर की अशांति।

किसी को धनवान बनाना आसान है, किसी को निर्धन बनाना आसान है, पर किसी के हृदय में शांति पैदा करना आसान नहीं। 'शांति' है क्या? कुछ लोग समझते हैं कि हमारी समस्याएं यदि समाप्त हो जाएं, तो शांति मिल जाएगी। युद्ध यदि समाप्त हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। ये सब अपना-अपना दृष्टिकोण है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। आंतरिक शांति का अनुभव तभी होगा जब आप अपने आपको जानेंगे। अपने वास्तविक स्वरूप को जब पहचानेंगे। आंतरिक शांति का संबंध आपके अपने अंदर की अनुभूति से है। अंदर की अनुभूति तभी संभव है, जब आप अपने आपको जानेंगे।

अगर किसी पुस्तक को खोलो तो वह अक्सर एक तरफ मोटी और दूसरी तरफ पतली होती है। पन्ने पलटते-पलटते जो हिस्सा पतला था वह मोटा और जो मोटा था वह पतला हो गया। जीवन भी एक ऐसी ही पुस्तक है, जिसके पन्ने एक तरफ से दूसरी तरफ तो पलटे जा सकते हैं, पर दूसरी तरफ से वापस पीछे नहीं पलटे जा सकते। इस जीवन की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, अगर उसे पढ़ना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है कि दुख नहीं, सुख पाना है। उस परम आनंद, परम शांति के लिए जीवन लिखा है और यह सबके अंदर मौजूद है। अगर इस पुस्तक को पढ़ना है तो 'हृदय की भाषा' को सीखो।

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ पाकिस्तान की चिंता

17 जुलाई का संपादकीय 'कहां गया लोकतंत्र' पढ़ा। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी पार्टी PTI पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान सरकार के फैसले की संयुक्त राष्ट्र ने आलोचना की है। वहां सत्ता के सारे सूत्र सेना के ही हाथ में रहते हैं। चुनाव में भी सेना का पूरा दखल होता है। हमने पहले भी देखा है कि कई बार सैन्य प्रमुखों ने चुनी गई सरकारों का तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और तानाशाही चलाई। पाकिस्तान की अस्थिरता का पूरा फायदा चीन उठा रहा है और सैन्य अधिकारियों को खरीद चुका है। चीन के अनुसार ही पाक सेना काम कर रही है। ऐसे में भारत को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

सुभाष, ईमेल से

■ बड़े बदलाव का भरोसा

यह पत्र 17 जुलाई के लेख 'बजट में छोटी बातों से बन जाएगी बात' से संबंधित है। लेखक ने बिलकुल सही कहा है कि अर्थव्यवस्था पर सही काम हो रहा है तो किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। हालांकि आम चुनाव में BJP ने उम्मीद से कम सीटें जीती हैं। हाल में हुए विधानसभा के उपचुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में यही लगता है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर निकलेगा।

बाल गोविंद, नोएडा

■ मिलकर करें काम

16 जुलाई के संपादकीय 'बिलों पर बढ़ेगी मेहनत' में कड़वा सच बयां किया गया है। BJP को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने तक बिलों को पास कराने में मेहनत करनी ही पड़ेगी। हालांकि अन्य दलों की मजबूरी भी सत्ता और उसकी निकटता है। ऐसे में कोई परेशानी होगी, कहना गलत होगा। हालांकि यह भी है कि पिछले 10 बरसों में सत्ताधारी दल ने जिस तरह से एक लाइन से बिल पास कराए हैं, इस बार वैसा होना मुश्किल है। अन्य दलों को अपने अजेंडे पर राजी करना फिलहाल BJP की मजबूरी रहेगी। लेकिन सहयोग करने वाले दल भी राष्ट्रहित में सौदेबाजी से बाज आएं और प्रासंगिक विषयों पर सरकार का समर्थन करके जन कल्याण में अपनी भागीदारी निभाएं।

अमृतलाल मारू, ईमेल से **nbtedit@timesgroup.com** पर अपनी राय नाम-पते के साथ भेज करें।

अंतिम पत्र

कभी ट्रंप को बोला था बेवकूफ, अब उन्हीं के साथ उपराष्ट्रपति की रेस में जेडी वेंस - खबर - नया चेहरा है, वक्त बदलते हैं, तो सुर भी बदल जाते हैं!

उमा रस्तोगी

आर.एन.आई. नं. 21657/71 सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी अनुमति के बिना सामग्री का पुनर्मुद्रण, वितरण, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के लिंक तथा संकेत प्रकाश हटाएं। । बाहरवाला प्रकाशन कार्यालय, नई दिल्ली-110020। से प्रकाशित तथा **राहुल आदित्य सिंह द्वारा टाइम्स ग्रुप, ऑफ इंडिया प्रेस लिमिटेड** और एसोसिएटेड प्रिंटर्स प्रा. लि., प्लॉट नं.2-ए, सेक्टर 16-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा मुद्रित। सीआईएन नंबर- U22120DL1946PLC000031, रजिस्टर्ड कार्यालय : दधीचि मैनेजमेंट हाउस, प्लॉट नं. 1, सेक्टर 16-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्र

जम्मू कश्मीर

आतंकी हमले

जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जारी हैं जिनमें लोगों की जानें गई हैं। जम्मू कश्मीर में हुई एक और त्रासद घटना में सुरक्षा बलों के चार जवान शहीद हुए हैं। एक मेजर समेत भारतीय सेना के चार सैनिक डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते समय शहीद हुए। इस घटना से सुरक्षा बलों के समक्ष उपस्थित चुनौतियां उजागर होती हैं तथा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के बारे में सरोकार गहरे होते हैं। व्यवस्था में सुधार के दावों के बावजूद आतंकी हमलों की बारंबारता और तीव्रता बढ़ रही है। सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या अलग-थलग घटनाओं के परिणामस्वरूप न होकर हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का संकेत है। आतंकी घटनाओं व लक्षित हत्याओं का जम्मू में केन्द्रित होना एक महत्वपूर्ण व चिन्ताजनक बदलाव है, जबकि यह दो दशकों से शांत था। 2021 में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद जम्मू में आतंकी हमलों और लक्षित हत्याओं में चिन्ताजनक उभार आया है। इसके कारण हिंसा खतरनाक स्तर तक बढ़ी है जिससे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका है। संभवत: कश्मीर में प्रभावी 'आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां' जम्मू के विशिष्ट और सामाजिक परिदृश्य के अनुकूल न हों। हालांकि, अतीत की रणनीतियों से प्राप्त सबकों से कुछ दिशा मिल सकती है, पर जम्मू में आतंक की नई लहर से निपटने के लिए नए आतंकवाद-विरोधी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय रूप से कश्मीर में पत्थरबाजी और सामाजिक अशांति में परिवर्तन आया है, पर उग्रवाद बना हुआ है और सक्रिय उग्रवादी समूहों ने अब जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाना शुरू किया है। इन समूहों को



अक्सर सीमापार से समर्थन मिलता है जिससे सुरक्षा परिदृश्य जटिल होता है। उग्रवाद को कुचलने के लिए अनेक सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद इन समूहों की मजबूती एक बड़ी बाधा है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक-राजनीतिक परिवेश भी हिंसा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐतिहासिक कतिपाइयों, राजनीतिक हाशियाकरण तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन उपलब्ध कराती हैं। हाशियाकृत अनुभव होने के बाद अनेक स्थानीय नौजवान हिंसा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे सुरक्षा बलों के लिए स्थिति और जटिल हो जाती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना टकराव के किसी दीर्घकालीन समाधान के लिए जरूरी है। सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या बढ़ने से वर्तमान रणनीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं और आतंकवाद-विरोधी तथा आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण के पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता उजागर होती है। हालांकि, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद की गई उम्मीद पूरी तरह सफल नहीं हुई है। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें जीवन्त सुरक्षा उपायों के साथ ही राजनीतिक संवाद तथा समुदाय की सहभागिता के प्रयास भी शामिल होने चाहिए। यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि हालिया लोकसभा चुनाव में तीन-चार दशक बाद जनता की भारी सहभागिता देख कर आतंकियों, चरमपंथियों व उनके समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे तत्व जनता को डरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संकर में डालना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने ऐसे 'स्थानीय तत्वों' की ओर संकेत किया है जो आतंकी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक रूप से ऐसे तत्वों पर लगाम लगाना भी जम्मू कश्मीर में शांति के लिए जरूरी हो गया है।

उपचुनाव नतीजों के संकेत

उपचुनाव नतीजों के अनेक संकेत हैं। विपक्ष के अनुसार इनसे सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा आंतरिक व बाहरी दबावों का सामना कर रही है।



कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)



उपचुनाव नतीजों के अनेक संकेत हैं। विपक्ष के अनुसार इनसे सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गठबंधन बनाए रखने के लिए भाजपा को आंतरिक व बाहरी दबावों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में हुई 13 सीटों के उप-चुनाव परिणामों से प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में मतदाताओं की राय समझने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरा कार्यकाल मिल गया। लेकिन आम चुनाव के एक महीने बाद हुए 13 सीटों के उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को 10 सीटों पर विजय मिली। इससे देश में राजनीतिक उथलपुथल पैदा हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 'इंडिया' समूह को मिले इन सकारात्मक परिणामों से सत्तारूढ़ गठबंधन की सत्ता पर पकड़ प्रभावित हो सकती है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सफलता मिली, पर वह बहुमत के 272 के आंकड़े से पीछे रह गई।

इसके परिणामस्वरूप उसे 'राजग' सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा। आशंका है कि इन स्थितियों में गठबंधन सहयोगी सरकार के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करेंगे तथा इसके कारण गठबंधन बनाए रखने के लिए भाजपा को समझौते करने पड़ सकते हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन में किसी अनिश्चितता की स्थिति या उसकी संभावना में विपक्षी दलों की हिम्मत बढ़ सकती है। पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटें ही प्राप्त कर सकी और इस प्रकार वह अपने दम पर 272 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में भाजपा को अपने 'राजग' सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस निर्भरता के कारण भाजपा के उन नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है जिनकी रूपरेखा उसने चुनाव के पहले ही तैयार कर ली थी। गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता के कारण भाजपा को उन खास मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ सकता है जो उसकी पहचान माने जाते थे। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं तथा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में सरकार के स्थायित्व पर भी संदेह के बादल मंडरा सकते हैं। संख्याबल के इस नाजुक संतुलन में विपक्ष संतुलन बिगाड़ने के प्रयास कर सकता है। उसका इरादा सत्तारूढ़ गठबंधन में असहज स्थितियां पैदा करने का है ताकि इसकी स्थिरता पर संदेह पैदा हो जाए। विधायिका में सीट खाली होने पर भारत का निर्वाचन आयोग स्वत: उप-चुनाव की घोषणा कर देता है। विधायिका में सीट खाली होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें निर्वाचित विधि-निर्माता की मृत्यु, इस्तीफा, अयोग्यता या उसकी सदस्यता समाप्त होना शामिल हैं।

संसद के किसी सदस्य की मृत्यु या उसके इस्तीफे की स्थिति में भी उपचुनाव होते हैं। इस स्थिति में केवल उस खाली सीट के मतदाता ही वोट दे सकते हैं। पिछले बुधवार को सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुए थे। इनमें पंजाब की एक, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखंड की दो, पश्चिम बंगाल की चार तथा मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक विधानसभा सीटें शामिल थीं। इन उपचुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी, आम आदमी पार्टी-आप तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम-द्रमुक, आदि ने अपने उम्मीदवार उतारे थे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकें। इन उपचुनावों में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को मिली व्यापक सफलता से विपक्ष के हौसले में काफी वृद्धि हुई है। ये उपचुनाव 'इंडिया' समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण और इसका एक प्रकार से परीक्षण थे क्योंकि लोकसभा चुनाव, 2024 के बाद वह पहली बार भारतीय जनता पार्टी-भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग का चुनाव मैदान में सामना करने जा रहा था। इन उपचुनावों में विपक्ष के क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 'इंडिया' समूह की एक प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी ने बंगाल की सभी चारों सीटों पर विजय प्राप्त की। उसकी यह विजय महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्साह से भरी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो-दो सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। इससे कांग्रेस की शक्ति इन राज्यों में और बढ़ गई है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम-द्रमुक ने तमिलनाडु में एक सीट जीती। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी-आप को जालंधर पश्चिम की सीट पर विजय मिली। इन विविधतापूर्ण नतीजों से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अनिश्चितता की भावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा केवल दो सीटें जीतने तथा बिहार में एक निर्दलीय के चुनाव जीतने से उपचुनाव परिणामों की जटिलता और बढ़ जाती है। यह आमतौर से माना जाता है कि उपचुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को सफलता मिलती है। इसे देखते हुए टीएमसी, द्रमुक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-आप की अपने सत्तारूढ़ राज्यों में विजय इनका उन राज्यों पर लगातार जारी नियंत्रण समझा जा सकता है।

टीएमसी के लिए ये उपचुनाव परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे क्योंकि केवल एक महीने पहले उसने पश्चिम बंगाल में 29 संसदीय सीटों पर विजय पाई थी, जबकि 2029 में इनकी संख्या 22 थी। लेकिन उत्तराखंड और बिहार में चीजें अलग थीं। यहां सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में हुए तीन उप-चुनावों में से दो पर विजय मिली है। परिणामों के बाद 68 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में कांग्रेस की संख्या फिर बढ़ कर 40 हो गई है। इससे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार स्थिर हो गई है। उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों और उनकी लोकप्रियता का महत्वपूर्ण परीक्षण होते हैं। इनके माध्यम से पार्टियां अपने समर्थन आधार तथा जनता की भावनाओं का पता लगाती है। अक्सर वे अपनी अभियान रणनीतियों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए उपचुनावों का प्रयोग करती हैं। इसका प्रभाव भावी चुनावों पर पड़ता है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनाव में कोई सीट जीतती है तो इससे उसकी सीटों की कुल संख्या बढ़ सकती है जिसका प्रभाव सरकार के स्थायित्व तथा उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है, हालांकि वह लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के कारणों की लगातार जांच भी कर रही है। हार के उभरते कारणों और मीडिया में आने वाली खबरों से लगता है कि भाजपा के भीतर वर्तमान रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं तथा संभवत: कुछ नेताओं के बीच इसके कारण तनाव है।

मीडिया में आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संभवत: आरएसएस और भाजपा के बीच तनाव है। इससे पार्टी को आरएसएस का समर्थन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा के भीतर और बाहर से पैदा दबावों के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन में भी तनाव व अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 'इंडिया' समूह के मजबूत प्रदर्शन से लगता है कि देश में राजनीतिक गत्यात्मकता बदल रही है। उल्लेखनीय है कि मतभेदों के बावजूद विपक्षी दलों के एकजुट होकर काम करने से उनको सफलता मिली है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दोनों तत्वों के कारण वे सफल हुए हैं।

विपक्ष के राजनीतिक रूप से मजबूत होने के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन कमजोर हो सकता है जिससे विपक्ष की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि, वर्तमान समय में भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर जीतना और हारना लोकतंत्र का अंग हैं। उपचुनावों के परिणामों का प्रभाव इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में खासतौर से दिख सकता है। 'इंडिया' समूह द्वारा उपचुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन से आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है। इन विधानसभा चुनावों से तय होगा कि विपक्ष को शक्ति मिलती है, अथवा वह कमजोर होता है।

र बन जाता।

पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां और भविष्य

जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2024 नजदीक आ रहा है, भारतीय पर्यटन उद्योग को समर्थन और रणनीतिक पहलों में वृद्धि की बड़ी उम्मीदें हैं।

दिव्या भाटिया
(लेखक, स्तम्भकार हैं)



पर्यटन हमेशा से दुनिया भर के देशों की आर्थिक वृद्धि और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, और भारत इसका अपवाद नहीं है। भारतीय पर्यटन ने लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, भले ही यह सरकारी नीतियों का प्राथमिक फोकस नहीं रहा हो। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार हुए हैं, लेकिन ये प्रयास सीमित रहे हैं। भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्राओं में तेज गिरावट के कारण महत्वपूर्ण गिरावट आई। इन चुनौतियों के बावजूद, उद्योग ने 2023 में सुधार के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, 2023 में 152 मिलियन घरेलू यात्री आए, जो 2022 के 123 मिलियन से लगभग 24त्न अधिक और 2019 के 144 मिलियन से लगभग 6त्न अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी पुनरुद्धार के संकेत मिले, 2023 में भारत से और भारत के लिए 63.9 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए, जो 2019 में देखे गए 64.2 मिलियन के करीब है और 2022 के 47 मिलियन से 35 प्रतिशत अधिक है। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी का अनुमान है कि भारत 2030 तक खर्च के मामले में चौथा सबसे बड़ा घरेलू यात्रा बाजार बन जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विमानन विश्लेषण फर्म संकेत देती है कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। डब्ल्यूटीटीसी ने बताया कि इस क्षेत्र ने 2023 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 19.13 ट्रिलियन (. 230 बिलियन) का योगदान दिया, जो 2019 के स्तर से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उद्योग में रोजगार में भी 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 43 मिलियन नौकरियों तक पहुंच गई। यह क्षेत्र के लचीलेपन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये अनुमान लगाते हैं कि भारतीय पर्यटन उद्योग में वृद्धि जारी रहेगी, और 2024 में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 21.15 ट्रिलियन (. 253 बिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग में नौकरियों में भी 2.45 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है, जो भारत में हर 11 नौकरियों में से एक है। सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, हाल के सरकारी बजटों में पर्यटन उद्योग को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2024 नजदीक आ रहा है, पर्यटन उद्योग सरकार से अधिक समर्थन और निवेश की उम्मीद कर रहा है।

द ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ज्योति मयाल को लगता है कि विदेशी प्रचार और प्रचार के लिए आवंटन में भारी कटौती करके उसे मात्र 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले साल के 100 करोड़ रुपये से कम है। वे कहती हैं, उद्योग बुनियादी ढांचे, विपणन और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कनेक्टिविटी, विरासत स्थलों और इको-टूरिज्म में निवेश से विकास को बढ़ावा मिल सकता है। संधारणीय प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जिम्मेदार पर्यटन के साथ संरेखित होता है। वीजा आवश्यकताओं को सरल बनाना और भारत आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश को प्रोत्साहित करना विदेशी पर्यटकों के आगमन को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

होटल और रेस्तरां एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी का कहना है कि पर्यटन और आतिथ्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है और इसे प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना लागत वाले होटलों और सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना निवेश आकर्षित करने और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए आवश्यक है। 7500 रुपये से अधिक के कमरे के किराए वाले होटलों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी को समाप्त करके, इसे 12 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में विलय करने से घरेलू और इनबाउंड पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ओटीओएआई) के अध्यक्ष रियाज मुंशी का कहना है कि आउटबाउंड पर्यटन क्षेत्र सकारात्मक नीतिगत बदलावों की उम्मीद कर रहा है।

उन्होंने कहा, एक प्रमुख उम्मीद आउटबाउंड टूर पैकेजों पर जीएसटी दरों में कमी की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा टीसीएस दरों की तुलना में बेहतर कर संग्रह (टीसीएस) नीतियों की उम्मीद है, जो विलीय और प्रशासनिक समस्याओं का कारण बन रही हैं।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के अध्यक्ष श्री राजीव मेहरा का मानना है कि वैश्विक मानचित्र पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। उनका कहना है, पर्यटन मंत्रालय को उद्योग के हितधारकों के साथ विदेशी यात्रा मार्ट में भागीदारी के लिए विपणन और प्रचार के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए, रोड शो आयोजित करने और टूर ऑपरेटरों को एमडीपू सहायता के लिए। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश का मानना है कि पर्यटन के आर्थिक और सामाजिक लाभों के बारे में सभी दिखावटी बातों के बावजूद, उद्योग दुखद रूप से उपेक्षित है। केवल बुनियादी ढांचे का विकास पर्याप्त नहीं है - यदि इस क्षेत्र को अपनी क्षमता का एहसास करना है तो इसे विशिष्ट प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

यात्रा और पर्यटन उद्योग हर साल बजट से पहले अपनी इच्छा सूची रखता है और, उस दिन हमेशा निराश होता है। उच्चतम जीएसटी स्लैब 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और ट्रैवल एजेंट/टूर ऑपरेटर सेटआॅफ का दावा करने के पात्र होने चाहिए। हवाई किराए को और अधिक किफायती बनाने के लिए विमानन ईंधन को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, वे कहते हैं।

आप की बात

आतंक से मुकाबला

हाल ही में हमारे पांच जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, हालांकि वीर जवानों ने आतंकी ठिकानों और आतंकियों को भी ढेर कर दिया। इससे पहले भी आतंकियों ने अद्यालुओं की बस को निशाना बनाया जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि, हमारे सुरक्षाबल मुस्तैदी से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें तथा उनके अड्डों का सफाया कर रहे हैं किन्तु आखिर कब तक ये खूनी खेल जम्मू-कश्मीर में चलता रहेगा। इसका अंत होना चाहिए ताकि वहां शान्ति स्थापित हो सके। सरकार को आतंकी तैयार करने और उनको शरण व सहायता देने वालों तक पहुँचने के लिए विशेष कार्य योजना बनानी होगी। सरकार को अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिये आतंक के स्रोतों तक पहुंच कर त्वरित और गंभीर प्रयास कर आतंक का समूल नाश करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को आतंक से मुक्ति दिलाने के प्रयास तेज करने होंगे। आतंक से मुकाबले के लिए जनता को भी प्रशिक्षित व मैनिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। यदि बहुसंख्य जनता अपने बीच छिपे आतंकियों तथा उनके समर्थकों के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए तो सुरक्षा बलों से बोझ कम होगा तथा आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पूरे देश में पैर टिकाने का स्थान भी नहीं मिलेगा।

- **महेश नेनावा,** इंदौर

शिक्षा में नवाचार

शिक्षा प्रणाली को नवाचार के माध्यम से सुधारना अब बेहद जरूरी हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे छात्रों में रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और स्वतंत्र सोच को विकसित करना भी शामिल होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य मस्तिष्क को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है न कि केवल तथ्यों को याद रखना। शिक्षा प्रणाली में नवीनतम तकनीकों और पद्धतियों को शामिल कर शिक्षकों को भी नियमित रूप से अद्यतित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों को सबसे बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षकों का ज्ञान और प्रशिक्षण ही छात्रों को श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण और अनुसंधान व विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा में नवाचार केवल छात्रों के भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवाचार से ही हम एक प्रगतिशील और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।

- **अवनीश कुमार गुप्ता,** आजमगढ़

ट्रंप पर हमला

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला हर लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। गनीमत है कि हमले में ट्रंप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित हैं। बैलेट से होने वाले चुनावों को बुलेट द्वारा बाधित करने के प्रयास विश्व के हर कोने में होने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की चुनावी भाषण के दौरान हत्या कर दी गई थी। उससे पूर्व भी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी सहित विश्व के कई नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। अब समूचे विश्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलकर आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना होगा। ट्रंप तो बच गए मगर फिर भी आतंकवादी मौके की तलाश में हर जगह मौजूद हैं। इस प्रकार बंदूक के जोर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करने के प्रयास अक्षम्य हैं। सुरक्षा व्यवस्थायें मजबूत करने तथा सुरक्षा बलों को आधुनिकतम तकनीकों से लैस करने के साथ लोकतांत्रिक समाजों में हिंसा और आतंकवाद पैदा होने के कारणों पर गंभीर विचार कर ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी जिनमें ऐसे तत्वों को विकास का अवसर ही न मिले। अब देखना होगा कि ट्रंप अपने देश में, खासकर नीजवानों में बंदूकों के आकर्षण से निपटने के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

इमरान की मुश्किलें

इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर सरकार विदेशी चंदा स्वीकार करने, गोपनीय दस्तावेज लीक करने, अमेरिका में गुप्त प्रस्ताव करने के तहत मौजूदा सरकार का तख्ता पलटने के प्रयास में 9 मई को पाकिस्तान में हुए दंगे कराने के मामले में केस शुरू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। इसके चलते इमरान खान पर देशद्रोह का आरोप और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ - पीटीआई पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है और एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। मौजूदा सरकार का मानना है कि पीटीआई और पाकिस्तान सरकार एक साथ काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन विडंबना है कि पाकिस्तान सरकार तथा सेना के तमाम प्रयासों के बावजूद आम जनता में इमरान खान की लोकप्रियता बनी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में बढ़ती अराजकता, आतंकवाद व आर्थिक बदहाली ने केवल उस देश, बल्कि भारत समेत सारी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। विफल राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है जहां वह लगातार आतंकी भेज रहा है।

- **दत्तप्रसाद शिरोड़कर,** मुंबई

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2024

महान नेता वही है, जो नया नेतृत्व तैयार करता है, न कि अपने अनुयायी। -रॉय टी. बेनेट

वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक किस्म की अनिश्चितता व ठहराव वाले दौर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया जाना देश की आर्थिक नीति व सुधारों की दिशा को मान्यता देने जैसा है। हालांकि असमानता और व्यापार घाटे संबंधी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

उपलब्धि और चुनौती

ऐसे समय में, जब विश्व के कई देशों में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बढ़ते सरकारी कर्ज, महंगाई व भू-राजनीतिक तनाव से पूरी दुनिया में अनिश्चितता छाई हुई है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के प्रति आश्वस्त करता है। बीते अप्रैल में आईएमएफ ने भारत की विकास दर के 6.8 फीसदी रहने की बात की थी, लेकिन अब उसका यह कहना कि अगले वर्ष यानी 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था सात फीसदी की दर से बढ़ सकती है, वाकई उत्साहजनक है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी पिछले महीने कहा था कि भारत संरचनात्मक बदलावों से गुजरते हुए आठ फीसदी की वृद्धि दर की राह पर बढ़ रहा है। दरअसल, भारत में, खासकर गांवों में रहने वालों के बढ़ते निजी उपभोग को अर्थव्यवस्था की गति की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय सांख्यकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के हालिया सर्वे से भी होती है। इसके अनुसार, पिछले ग्यारह वर्षों में ग्रामीण परिवारों की खपत में इजाफा हुआ है। यानी 2011-12 में गांवों में जो प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1,430 रुपये था, वह 2022-23 में करीब 3,773 रुपये हो गया। हालांकि शहरों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का 71 फीसदी ज्यादा होना असमानता की बढ़ती चुनौती को भी दर्शाती है। हालांकि, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023 के 3.3 फीसदी की तुलना में 0.1 फीसदी सुस्त रहने की बात की जा रही हो, तब रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का 2025 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहना, एक सकारात्मक संकेत है। लिहाजा, इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए कि आईएमएफ की रिपोर्ट भारत की आर्थिक नीतियों और सुधारों की दिशा को मान्यता तो देती ही है, यह



सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों व उनकी प्रभावशीलता का भी प्रमाण है। वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों के अलावा उद्यमिता व डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन से ये क्षेत्र भी देश के विकास की कहानी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, चुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश, उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति और मध्यम वर्ग के विस्तार ने भी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि निर्यात की तुलना में आयात के ज्यादा गति से बढ़ने से व्यापार घाटे का बढ़ता परिणाम जरूर एक चुनौती बना हुआ है।

जीवन धारा



मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई महान हो सकता है, क्योंकि महानता सेवा से निर्धारित होती है। आपके पास केवल अनुग्रह से भरा दिल और एक प्यारी आत्मा चाहिए।

सही काम करने के लिए हर समय सही समय होता है

हमने पक्षियों की तरह हवा में उड़ान भरी है और मछलियों की तरह समुद्र में तैरा है, लेकिन अभी तक हमने भाइयों की तरह पृथ्वी पर चलने का सरल कार्य करना नहीं सीखा है। हमें या तो भाइयों की तरह एक साथ रहना सीखना होगा, या फिर हम मूर्खों की तरह एक साथ मरेंगे। और इससे कहीं न कहीं एक दूसरी बुराई पैदा होती है, जो आधुनिक दुनिया को परेशान कर रही है। वह बुराई है गरीबी। विश्व में लगभग दो-तिहाई लोग रात में भूखे पेट सोते हैं। वे खराब घरों में रहते हैं, मैले-कुचैले कपड़े पहनते हैं और कुपोषित हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास न तो घर है और न ही बिस्तर। आपने देखा होगा कि कई लोग शहरों के फुटपाथ और



गांवों की धूल भरी सड़कों को बिस्तर बना लेते हैं। और गरीबी से त्रस्त संतानों में से अधिकांश ने कभी किसी चिकित्सक से इलाज नहीं कराया है। गरीबी के बारे में यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि हमारे पास इससे छुटकारा पाने के लिए संसाधन हैं। अमीर देशों को अपने धन का उपयोग अविकसित लोगों को विकसित करने के लिए करना चाहिए। जो लोग शांति पसंद करते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से संगठित होना सीखना चाहिए। हमें इस पीढ़ी में न केवल बुरे लोगों के घृणित शब्दों और कार्यों के लिए, बल्कि अच्छे लोगों की भयावह चुप्पी के लिए भी पश्चाताप करना होगा। यहां जरूरत है उस साहस की, जो भय का सामना करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है।

एक सामाजिक आंदोलन, जो सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाता है, वह सिर्फ विद्रोह है, लेकिन एक आंदोलन, जो लोगों और संस्थाओं, दोनों को बदलता है, वह क्रांति है। हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई महान हो सकता है, क्योंकि महानता सेवा से निर्धारित होती है। आपके पास केवल अनुग्रह से भरा दिल और एक प्यारी आत्मा चाहिए। कोई आदमी तब मर जाता है, जब वह सही बात के लिए खड़ा होने से इन्कार करता है। सही काम करने के लिए हर समय सही समय होता है। ठीक है कि कानून किसी का दिल नहीं बदल सकता, लेकिन यह हृदयहीन लोगों पर लगाम लगा सकता है। हमें अपनी सीमित दृष्टि के अनुरूप पूरी विनम्रता से बोलना चाहिए, लेकिन हमें बोलना जरूर चाहिए। कभी भी, सही काम करने से डरना नहीं चाहिए, खासकर तब, जब किसी व्यक्ति या जानवर की भलाई दांव पर लगी हो। अपने जीवन का जो भी काम हो, उसे अच्छे से करना चाहिए। अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति को गहनता से और आलोचनात्मक ढंग से सोचना सिखाती है। बुद्धिमत्ता और चरित्र यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। एक महान राष्ट्र अंततः एक दयालु राष्ट्र होता है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र तब तक महान नहीं हो सकता, जब तक वह असहाय लोगों की चिंता न करे। लोकतंत्र पृथ्वी पर सरकार का सबसे महान रूप है। निकट भविष्य में प्रेम और भाईचारे के दीप्तिमान सितारे अपनी जगमगाती सुंदरता के साथ हमारे महान राष्ट्र पर चमकेंगे।

वंचितों की सेवा ही महानता

मानव समाज प्रगति के नित नए सोपान चढ़ता जा रहा है, लेकिन अब भी उसमें विश्व बंधुत्व की भावना नहीं पनप पाई है। तमाम प्रगति के बावजूद इस धरती पर बहुत सारे वंचित लोग हैं, जिनकी गरीबी को संपन्न लोग खत्म कर सकते हैं। ऐसे असहाय लोगों की सेवा करके, उनके साथ खड़े होकर कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र महान बन सकता है।

सूत्र

ट्रंप ने वेंस को क्यों चुना

करीब पिछले एक दशक से वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहे ट्रंप ने हालिया हमले से उबरते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। महज 39 वर्ष के तेज-तर्रार जेडी वेंस में शिष्यता का भाव इस कदर भरा है कि वह ट्रंप के दुश्मन को अपना दुश्मन मानते हैं। वेंस का नामांकन यह बताता है कि ट्रंपवाद जारी रहेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। इससे पहले के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन पार्टी की एकता को मजबूत करने, जिस प्रांत में पार्टी की स्थिति डांवाडोल हो, उसे अपने पाले में लाने और वाशिंगटन से बाहर के राष्ट्रपति को सत्ता संचालन में मदद करने के लिए चुना जाता था। इन मानदंडों पर वेंस खरे नहीं उतरते। ट्रंप ने जब वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो उनके मन में संभवतः 2024 ही नहीं था, बल्कि वह 2028 और उससे आगे के बारे में सोच रहे थे।

पिछली बार जब ट्रंप ने अपने साथी का चुनाव किया था, तो वह ज्यादा चिंतित थे। तब कई रिपब्लिकन, खासकर सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादी, उन्हें संदेह की नजर से देखते थे। ट्रंप ने तब माइक पेंस को चुना, ताकि उनका भय कम हो सके, क्योंकि पेंस के ईसाई मतदाताओं से घनिष्ठ संबंध थे। विचार यह था कि वह ट्रंप को अंदरूनी लोगों और सत्ता के बिचौलियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप-पेंस की जोड़ी छह जनवरी, 2021 तक कायम रही। अब हमलावर की गोली से बाल-बाल बचने और सांविधानिक रूप से एक और कार्यकाल तक सीमित रहने के कारण ट्रंप स्वाभाविक तौर पर वफादारी और विरासत को तवज्जो दे रहे हैं।



मैथ्यू कॉन्टिनेटी
द न्यूयॉर्क टाइम्स

वेंस में ट्रंप और ट्रंपवाद के प्रति काफी जोश है और इसकी संभावना नहीं है कि वह उपराष्ट्रपति निवास को आप्रवासन समर्थक और हस्तक्षेप करने वाले रिपब्लिकन का ठिकाना बनने देंगे। वह 2020 के चुनाव के बाद से ही ट्रंप के आचार-व्यवहार का अनुसरण तो कर ही रहे हैं, आलम यह है कि वह ट्रंप के दुश्मन को अपना भी दुश्मन मानते हैं। ट्रंप को वेंस की जीवनी भी पसंद आई होगी। गरीबी में पले-बढ़े वेंस 9/11 आतंकी हमले के बाद मरीन में शामिल हुए, बेस्टसेलिंग आत्मकथा लिखी और व्यवसाय में कामयाब हुए। श्रमिक वर्ग से जुड़ी उनकी जड़ें औद्योगिक पतन के शिकार इलाकों (रस्ट बेल्ट) के उन भूले-बिसरे लोगों को आकर्षित कर सकती हैं, जो ट्रंप के अभियान के केंद्र में हैं।



दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वेंस के पक्ष में जाती है, वह है उनकी उम्र। रिपब्लिकन इस साल युवा पुरुष मतदाताओं के बीच अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और वेंस पार्टी को इस बढ़ते लाभ का फायदा उठाने में मदद कर सकते हैं। रिचर्ड निक्सन जब 39 साल के थे, तो ड्वाइट आइजनहावर ने उन्हें 1952 में अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना था। निक्सन 22 वर्षों तक अमेरिकी राजनीति के केंद्र में रहे।

हाल ही में 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (एमएजीए) आंदोलन में शामिल हुए वेंस ने इस वर्ष रिपब्लिकन के प्रीमियर में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली के समर्थकों की विदेश और आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। वेंस वाशिंगटन के लिए नवागंतुक हैं। अगस्त में वह 40 वर्ष के हो जाएंगे और अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपतियों में से एक होंगे। सीनेट में उनके दो साल ही हुए हैं, इसलिए वह अब तक के सबसे कम अनुभवी उपराष्ट्रपति होंगे। ट्रंप उनके अनुभवी गुरु होंगे और वेंस उनके प्रशिक्षु होंगे।

आम तौर पर ट्रंप को एक धैर्यवान गुरु या दीर्घकालिक योजनाकार के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन हाल ही में उन्हें दोषी ठहराए जाने और उनकी हत्या के प्रयास ने इस चुनाव में दांव बढ़ा दिए हैं और इसलिए वह न केवल जीतना जरूरी समझते हैं, बल्कि कुछ स्थायी काम करना भी चाहते हैं। वेंस का चुनाव इस बात का भी संकेत देता है कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य को कैसे देखते हैं। यदि वेंस उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो वह 2028 में रिपब्लिकन प्रत्याशी के लिए सबसे अग्रणी दावेदार होंगे। निश्चित रूप से उनके नामांकन को चुनौती मिलेगी, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रवाद, लोकलुभावन और 'अमेरिका प्रथम' के अपने एजेंडे पर कायम रहे।

येल लॉ स्कूल से स्नातक वेंस शायद एमएजीए के सबसे मुखर समर्थक हैं। वे वित्तीय क्षेत्र, कॉर्पोरेट एकाधिकार, मुक्त व्यापार, वैश्विक हस्तक्षेप और अवैध आव्रजन के आलोचक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अनुपस्क विधेयक का विरोध किया, जिसके तहत इस वर्ष यूक्रेन, इस्राइल और ताइवान को सैन्य सहायता प्रदान की गई।

पिछले हफ्ते जब वेंस ने वाशिंगटन डी.सी. में राष्ट्रीय रूढ़िवाद सम्मेलन में भाषण दिया, तो उनका एक स्टार की तरह स्वागत किया गया। उन्होंने सहजता से अपनी बात रखी। उन्होंने श्रोताओं में मौजूद प्रमुख नीति विशेषज्ञों का नाम लिया, मसलन एलब्रिज कोल्बी, जो विदेश नीति को प्राथमिकता देने के समर्थक हैं, जो चीन को निर्यातित करने के लिए दिखेगी प्रतिबद्धताओं को सीमित करेंगी, और ओरेन कैस, जो उदारवादी अर्थशास्त्र के आलोचक हैं।

वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रवादी लोकलुभावनवाद के बढ़ते प्रभाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'भले ही हम यूक्रेन सहायता पर बहस नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में मायने रखता है।' उपराष्ट्रपति पद पर उनकी पदोन्नति से एमएजीए वेस्ट विंग की गारंटी होगी और घरेलू विनिर्माण तथा रक्षा औद्योगिक आधार के पुनर्निर्माण के लिए कठोर विदेश नीति और सरकारी कार्रवाई के पैरोकार मजबूत होंगे। आप्रवासन के लिए उन्होंने सबसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'अमेरिकी लोकतंत्र के लिए असली खतरा यह है कि अमेरिकी मतदाता कम प्रवासन के लिए मतदान करते रहते हैं और हमारे राजनेता ज्यादा आप्रवासन को मंजूरी देते रहते हैं। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आप्रवासन ने हमारे समाजों को गरीब, कम सुरक्षित, कम समृद्ध और कम उन्नत बना दिया है।' इसलिए अमेरिकी नेताओं को अमेरिका के लोगों की देखभाल करनी चाहिए।' ट्रंप ने करीब एक दशक तक वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। वेंस के नामांकन से पता चलता है कि ट्रंप की शैली, उनकी नीतियां और हर जाति और नस्ल के गैर-कॉलेज-शिक्षित मतदाताओं के लिए ट्रंप की अपील आने वाले दशकों तक रिपब्लिकन पार्टी पर राज करेगी।

©The New York Times 2024

दूसरा पहलू

जब यूरोप के कई देशों में पर्यटकों पर नए-नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तब डेनमार्क की राजधानी में पर्यटक पुरस्कृत हो रहे हैं।

पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों को कोपेनहेगन दे रहा उपहार

वेनिस में दिन में घूमने वाले पर्यटकों पर नया शुल्क लगाया गया है। बार्सिलोना में छुट्टियों के मौसम में सैलानियों को किराये पर कमरे लेने पर प्रतिबंध है। स्पेन के मशहूर द्वीप म्जोर्का में शराब पर बंदिश लगा दी गई है। जब यूरोप के अलग-अलग देशों में पर्यटकों पर नए-नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तब डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के प्रशासन ने उन पर्यटकों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाएंगे। 15 जुलाई से कोपेनहेगन आने वाले जो पर्यटक साइकिल और रेल से सफर कर सफाई के अभियानों में भाग लेंगे, उन्हें होटल की बुकिंग में सहूलियत मिलेगी, म्यूजियम का टूर कराया जाएगा, मुफ्त भोजन के साथ दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी।



सेयेलन येगिंसू

हाल के वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर पर्यावरण के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया है, उसी को देखते हुए डेनमार्क में यह अनूठा कदम उठाया जा रहा है।



15 जुलाई से कोपेनहेगन आने वाले जो पर्यटक साइकिल और रेल से सफर कर सफाई अभियानों में भाग लेंगे, उन्हें होटल की बुकिंग में सहूलियत मिलेगी, म्यूजियम का टूर कराया जाएगा, मुफ्त भोजन के साथ दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

लंदन स्थित मार्केट रिसर्च ग्रुप केंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के तहत कोपेनहेगन के 81 फीसदी लोगों ने कहा कि वे पर्यावरणीय टिकाऊ विकास की दिशा में काम करना चाहते हैं, पर वास्तविक तौर पर 22 फीसदी लोगों ने ही जलवायु परिवर्तन के बीच अपनी सोच बदली है। कोपेनहेगन की एक संस्था कोपेनपे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लोगों की कथनी-करनी के बीच की सोच को बदलने की दिशा में काम कर रही है। उसने इस संदर्भ में कुछ कदम भी उठाए हैं। राजधानी के पर्यटन विभाग बंडरफुल कोपेनहेगन के प्रमुख कार्यकारी माइकल हानसेन कहते हैं कि हाल के वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर पर्यावरण के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया है, उसी को देखते हुए डेनमार्क में यह अनूठा कदम उठाया जा रहा है। हम पर्यटन को पर्यावरणीय बोझ की जगह सकारात्मक बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं।

नई घोषणा के मुताबिक, जो लोग कोपेनहिल तक साइकिल या ट्रेन से आएंगे, उन्हें रूफटॉप हिल तक मुफ्त में जाने दिया जाएगा। ऐसे ही, जो लोग तख्तियों के सहारे समुद्र की लहरों से खेलते हैं, वे अगर समुद्रतट की सफाई के आधे घंटे के अभियान से जुड़ें, तो कोपेनहेगन सर्फ स्कूल उन्हें मुफ्त लंच मुहैया कराएगा। राजधानी स्थित नेशनल गैलरी ऑफ डेनमार्क प्लास्टिक की चीजों से कलाकृतियां बनाने संबंधी एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान पर्यावरण के अनुकूल लगभग 20 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डेनमार्क की राजधानी में चलाए जा रहे इन अभियानों के प्रति हानसेन बेहद आशान्वित हैं। 'हम चाहते हैं कि कोपेनपे के जरिये चलाए जा रहे इन अभियानों का असर डेनमार्क के दूसरे शहरों समेत दुनिया के दूसरे शहरों पर भी पड़े', वह कहते हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

पर्यटन स्थल

विदेशी पर्यटकों की रुचि सबसे ज्यादा ताजमहल में है। पर कुतुब मीनार ने आगरा के किले को जरूर पीछे छोड़ दिया है।

ताजमहल	6,81,339
कुतुब मीनार	2,20,017
आगरा किला	2,18,144
हुमायूं का मकबरा	1,16,904
चांद बावड़ी	96,080

आंकड़े बीत वर्ष 2024 के और सिर्फ विदेशी पर्यटकों से संबंधित हैं। चोट : ASI

भरत को हिरण के बच्चे से काफी लगाव हो गया था। वह गुम हो गया, तो उसे काफी खोजा, पर नहीं मिला। अंत समय में भी वह मृग को याद करते रहे।

हिरण में हुई भरत की आसक्ति

भरत भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। उनके संबंध में कथा है कि वह जब पुलह ऋषि के आश्रम में रहते थे, तो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी भी सुध-बुध भी नहीं रहती थी।

एक बार एक माद्दा हिरण शेर से बचने के लिए गंडकी नदी में कूद गई। वह गर्भवती थी, तो उसने पानी में बच्चे को जन्म दिया। बाहर निकलकर हिरणी ने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर भरत का मन करुणा से भर उठा।

उन्होंने हिरण के बच्चे को पानी से निकाला और उसका पालन-पोषण करने लगे। हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह नित्य का भजन-पूजन भी भूल गए। एक दिन हिरण का बच्चा गुम हो गया। उसको ढूंढने के लिए भरत बेचैन हो उठे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो वह अंत समय में भी हिरण के बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे। इस वजह से उन्होंने अगला जन्म मृग के रूप में लिया, लेकिन भगवान की कृपा के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहीं। वह पुलह ऋषि के आश्रम के आसपास ही रहते और भगवान का स्मरण करते रहते थे।



अंतर्यात्रा
संकलित

अंत में उन्होंने गंडकी नदी में स्नान कर मृग शरीर को त्यागा और इन्सान के रूप में जन्म लेकर फिर भगवान की भक्ति कर मुक्ति प्राप्त की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 07 अप्रैल, 1956

विंध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाने की पुनः मांग

विंध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाने की पुनः मांग

इलाहाबाद दिनांक 6 अप्रैल संवाददाता रहे, गये, पास सभाएं एवं जनसभा एवं जनसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य पुनर्गठन बिल पर बहस के दौरान मांग की गई कि विंध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। एक संशोधन में कहा गया कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए।

निर्यात बढ़ाने के लिए नई कवायद का वक्त



नई गठबंधन सरकार निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लक्ष्य को लेकर मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है।

जयंतीलाल भंडारी — विदेश व्यापार

नई गठबंधन सरकार वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लक्ष्य को सामने रखकर मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है। हाल ही में नई दिल्ली में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का संगठन) में भारत ने नई जान फूंकने की कोशिश की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए बिम्सटेक के देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने की पहल नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट तथा सागर नीति का ही हिस्सा है। इसी तरह भारत ने रूस सहित मित्र देशों और विभिन्न विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीतों से कारोबार बढ़ाने की नई कवायद शुरू की है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे के दौरान द्विपक्षीय बातचीतों से विदेश व्यापार की नई संभावनाएं आगे बढ़ाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातों के बाद जारी हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने, व्यापार में संतुलन लाने, गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करने और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू)-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाएं तलाशने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल कर एक द्विपक्षीय निपटान प्रणाली स्थापित करने और पारस्परिक निपटान प्रक्रिया में डिजिटल वित्तीय उपकरणों को लाने की योजना बनाने की बात कही है। ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 2023 में दोनों देशों के बीच लगभग 2.93 अरब रुपये का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ऑस्ट्रिया के लिए भारत यूरोपीय संघ के बाहर इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है।

पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्रप्रमुखों को बुलाया गया था। हाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद तीस्ता नदी के जल प्रबंधन, समुद्री अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेक्टर सहित 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मद्देनजर कोलंबो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और भारत से दिए गए 60 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वर्ष 2022 में जब श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने 3.5 अरब डॉलर की मदद देकर हमें आर्थिक संकट से उबारा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाल में जी-7 के शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश भारत की अहमियत दिखाई दी। भारत के लिए सबसे ठोस लाभ जी-7 की उस प्रतिबद्धता से उपजा, जिसमें कहा गया कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को बढ़ावा दिया जाएगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा गत वर्ष भारत में जी 20 शिखर बैठक के समय की गई थी।

सरकार को आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति अपनानी होगी। साथ ही भारत को ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इस्राइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्र अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। इस पर भी काम करना होगा कि पिछले वर्ष जी-20 में जिस 55 देशों वाले अफ्रीकी संगठन को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है, उन देशों में निर्यात बढ़ाने होंगे। उम्मीद है कि पिछले दिनों रूस, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और विभिन्न देशों के साथ की गई द्विपक्षीय वार्ताएं लाभप्रद सिद्ध होंगी। ऐसे में निश्चित रूप से भारत विदेश व्यापार बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों से वर्ष 2030 तक माल एवं सेवाओं के दो लाख करोड़ डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।

edit@amarujala.com